सबका साथ–सबका विकास–सबका विश्वास

सुशासन के 3 वर्ष

नये भारत का नया उत्तर प्रदेश

मथुरा

मथुरा

POWERING
NEW INDIA

चहुँमुखी विकास के तीन वर्ष

उत्तर प्रदेश अब तक के अपने सबसे बड़े 5 लाख 12 हजार करोड़ रु. के बजट के साथ 'वन ट्रिलियन डालर' इकोनॉमी बनने की दिशा में तेजी से अग्रसर है। 19 मार्च, 2020 को वर्तमान सरकार के तीन वर्ष पूर्ण हो गये। असीमित क्षमताओं वाले उत्तर प्रदेश में तीन वर्ष पूर्व प्रत्येक क्षेत्र में अव्यवस्था एवं अराजकता का बोलबाला था। 19 मार्च, 2017 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने देश के इस सबसे बड़े राज्य का दायित्व योगी आदित्यनाथ के कंधों पर डाला। जनता से किये गये वायदों को पूरा करना आसान नहीं होता, वह भी ऐसी स्थिति में जब प्रदेश की आर्थिक एवं प्रशासनिक स्थिति जर्जर हो, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी दूरदृष्टि एवं प्रशासनिक कौशल से प्रदेश के विकास का मार्ग प्रशस्त कर दिया।

सरकार ने पहली कैबिनेट बैठक में ही निर्णय लेकर 86 लाख से अधिक लघु एवं सीमांत किसानों का 36 हजार करोड़ रु. का ऋण माफ कर दिया। प्रदेश में कानून का राज स्थापित करना, पूंजी निवेश और बुनियादी सुविधाओं का विकास एवं विस्तार करना एक बड़ी चुनौती थी, परंतु अपनी रचनात्मक सोच और सुशासन से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस दिशा में मजबूती से कदम बढ़ाये। अपराधियों में कानून का ऐसा खौफ पैदा हुआ कि वे पुलिस के सामने समर्पण करने लगे। अवैध स्लाटर हाउस बंद हो गये। बालिकाओं को एंटी रोमियो स्क्वायड से सुरक्षा मिली, अपहरण उद्योग का खात्मा हुआ।

प्रदेश सरकार ने तीन वर्षों में पारदर्शी प्रक्रिया के अन्तर्गत लगभग 3 लाख लोगों को सरकारी नौकरियां दी हैं। प्रदेश में औद्योगिक वातावरण सृजन एवं निवेश हेतु सरकार ने साल भर के अंदर ही अभूतपूर्व इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन किया, जिसमें 4.68 लाख करोड़ रु. के निवेश सम्बन्धी एम.ओ.यू. हस्ताक्षरित हुए। इसी कड़ी में प्रथम और द्वितीय ग्राउण्ड ब्रेकिंग सेरेमनी व अन्य माध्यमों से रु. 2.5 लाख करोड़ का निवेश आने से प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से 33 लाख से अधिक रोजगार के अवसर सृजित हुए। इसके अलावा ओडीओपी योजना से जहां 10 लाख लोगों को रोजगार मिला, वहीं कौशल विकास प्रशिक्षण से 1.71 लाख बेरोजगार स्वरोजगार से जुड़े। डिफेंस एक्सपो में यूपीडा के जरिए हुए 23 एम.ओ.यू. से रु. 50 हजार करोड़ के निवेश के साथ ही 5 लाख से अधिक रोजगार सृजित होंगे।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की 'एक जनपद–एक उत्पाद' (ओडीओपी) योजना की परिकल्पना को राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति मिली। उत्तर प्रदेश के सभी 75 जनपद अपने–अपने विशिष्ट उत्पादों के लिए जाने जाते हैं। इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को अब तक **रु. 8875 करोड़ से अधिक** के ऋण वितरित किये गये। इससे उत्पादों को नया बाजार मिला और जिलावार उत्पादों की मैन्यूफैक्चरिंग के साथ ही रोजगार में वृद्धि हुई।

तीन वर्ष में ही प्रदेश कई क्षेत्रों में देश में शीर्ष पर पहुंच गया। कौशल विकास नीति, राज्य स्वास्थ्य नीति लागू कर एवं मानव–वन्य जीव संघर्ष को आपदा घोषित करने में उत्तर प्रदेश, देश का पहला राज्य बना। ई–मार्केट (जेम) के अंतर्गत सर्वाधिक खरीददारी करने में भी टाप बायर पुरस्कार हासिल कर देश में पहला स्थान प्राप्त किया। प्रधानमंत्री आवास योजना में 09, मनरेगा में 07, रूर्बन मिशन में 02, आजीविका मिशन में 01, ग्राम स्वराज अभियान में 01 और एन.आई.आर. डी.पी. में 01 पुरस्कार प्राप्त हुआ। तीन वर्ष में ही मातृ मृत्यु दर में सबसे अधिक 30 प्रतिशत गिरावट आई। पोषण माह के लिए सर्वोच्च पुरस्कार मिला। स्वच्छता सर्वेक्षण में प्रदेश के 14 निकाय सम्मानित हुए एवं सर्वाधिक तिलहन उत्पादन के लिए कृषि कर्मण पुरस्कार मिला। द मिलियन फार्मर्स स्कूल (किसान पाठशाला) योजना जैसे अभिनव प्रयोग को देश–विदेश में लागू करने की अनुशंसा की गई। महिला सशक्तीकरण के तहत वन स्टाप सेंटर स्थापित करने के लिए नारी शक्ति पुरस्कार, डिजिटल भूमि प्रणाली के लिए राष्ट्रीय ई–गवर्नेंस पुरस्कार, अधिक विद्युत संयोजन के लिए सौभाग्य योजना पुरस्कार, दिव्यांगजन सशक्तीकरण के लिए 03 राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिले। दुग्ध, चीनी, गन्ना, खाद्य उत्पादन में भी प्रदेश प्रथम स्थान पर है। देश में सबसे ज्यादा चिकित्सा संस्थानों की स्थापना एवं संचालन में भी प्रदेश अग्रणी है। इससे प्रदेश की पहचान 'विकसित प्रदेश' के रूप में हो रही है।

वर्षों से पूर्वांचल में इंसेफ्लाईटिस महामारी का रूप ले चुकी थी। राज्य के 38 जनपदों में हर बारिश में नमीपूर्ण ठंड में यह बीमारी बच्चों के लिए घातक सिद्ध हो रही थी। योगी सरकार ने इस पर पूरा ध्यान केन्द्रित किया। इसके परिणामस्वरूप इन रोगों के मामलों में 56 फीसदी कमी हुई और मृत्यु दर में 90 प्रतिशत की कमी आई है। इसके अलावा सभी को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए नये मेडिकल कालेज खोले गये। जिला चिकित्सालयों को उच्चीकृत कर गंभीर रोगों की निःशुल्क जांच के साथ ही जीवन रक्षक दवाएं उपलब्ध करायी गईं।

प्रदेश में पहली बार संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा निर्धारित सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में 2 अक्टूबर, 2019 (गांधी जयंती) से 36 घंटे का विधान मंडल का अनवरत ऐतिहासिक सत्र आयोजित किया गया। जनवरी माह में 23वाँ राष्ट्रीय युवा उत्सव–2020 आयोजित किया गया। 'उत्तर प्रदेश दिवस' समारोह मनाने की शुरुआत हुई। प्रदेश के 27 जनपदों में गंगा यात्रा के माध्यम से माँ गंगा की निर्मलता एवं अविरलता के प्रति जन जागरूकता पैदा की गयी। प्रदेश में पहली बार लखनऊ में 11वें डिफेंस एक्सपो का आयोजन वृहद स्तर पर किया गया।

योगी सरकार ने पर्यटन को बढ़ावा देने तथा निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए हवाई कनेक्टिविटी पर विशेष जोर दिया। पहले प्रदेश में जहां मात्र 02 एयरपोर्ट थे, जिनसे 25 गन्तव्य स्थल जुड़े थे, परन्तु अब राज्य में एयरपोर्ट की संख्या बढ़कर 08 और गन्तव्य स्थलों की संख्या 55

हो गयी है। 11 अन्य एयरपोर्ट का विकास एवं जेवर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थापित करने की कार्यवाही गतिमान है। सड़क कनेक्टिविटी, आतिथ्य उद्योग के विकास, हवाई सेवा से सम्बद्धता और सुरक्षा सुनिश्चित करने से पर्यटन उद्योग के स्वरूप में 10 गुना वृद्धि हुई है। अयोध्या, मथुरा और काशी जैसे नगरों में सांस्कृतिक, धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा दिया गया है। अयोध्या में दीपोत्सव के रिकार्ड पर रिकार्ड बने। मथुरा में कृष्णोत्सव एवं रंगोत्सव का आयोजन किया गया। वर्ष 2019 को प्रयागराज कुम्भ ने तो पूरे विश्व का ध्यान अपनी ओर खींचा। इस दौरान 25 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने गंगा में डुबकी लगायी। साफ–सफाई, परिवहन और कलाकारी में विश्व रिकार्ड बने। बौद्ध सर्किट को विकसित कर बौद्ध पर्यटन को भी एक बड़े पर्यटन उद्योग में बदला जा रहा है। इससे पर्यटकों में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है।

जहां तक बुनियादी सुविधाओं की बात है तो महज तीन सालों में ही एक्सप्रेस–वे आकार लेने लगे। पिछली सरकार से आधे–अधूरे मिले आगरा–लखनऊ एक्सप्रेस–वे का कार्य तो पूर्ण ही कराया, 341 कि.मी. लंबे एक नये पूर्वांचल एक्सप्रेस–वे भी इस वर्ष के अन्त तक जनता को समर्पित कर दिया जायेगा। 92 कि.मी. लंबे गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस–वे की प्रक्रिया गतिमान है। 297 कि.मी. लंबे बुंदेलखंड एक्सप्रेस–वे की कार्य प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। मेरठ से प्रयागराज तक 640 कि.मी. लम्बे एक्सप्रेस–वे के निर्माण का बड़ा निर्णय लिया गया है। लखनऊ मेट्रो के प्रथम चरण का संचालन पूर्ण कर द्वितीय चरण के कार्य के लिए प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी गयी है। कानपुर मेट्रो रेल का कार्य प्रगति पर है। आगरा, प्रयागराज, गोरखपुर एवं वाराणसी में मेट्रो रेल/रैपिड अर्बन ट्रांसपोर्ट मोबिलिटी सिस्टम के लिए कार्य किया जा रहा है।

आंकड़े सच का आइना दिखाते हैं। वर्ष 2014–15 में सकल घरेलू उत्पाद में 4.0 प्रतिशत वृद्धि अनुमानित थी। वर्ष 2014–15 में कृषि, पशुधन, वन, मत्स्य में –0.9 प्रतिशत, बिजली, विनिर्माण, गैस, जलापूर्ति और निर्माण कार्य में –2.0 प्रतिशत, सेवा क्षेत्र में 9.0 प्रतिशत वृद्धि हुई थी। वर्ष 2014–15 में प्रदेश का सकल घरेलू उत्पाद 8 लाख 34 हजार 432 करोड़ रु. अनुमानित रही। प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय वर्ष 2014–15 में रु. 42,267 थी, जो वर्तमान में बढ़कर रु. 70,419 हो गई है।

योगी सरकार द्वारा गांव, गरीब, किसान, महिला, मजदूर, नौजवान सहित सभी के हित की योजनाएं लागू की जा रही है। स्पष्ट है कि 23 करोड़ लोगों की विशाल आबादी वाला **उत्तर प्रदेश सकारात्मक उत्पादक परिवर्तन लाते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी की भावनानुरूप वन ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी बनने की ओर अग्रसर है।**

भारत सरकार का विज़न नये भारत का निर्माण

जम्मू - कश्मीर का भारत से पूर्ण एकीकरण

- मोदी सरकार ने ऐतिहासिक कदम उठाते हुए जम्मू-कश्मीर से जुड़े अनुच्छेद 370 के विशेष प्रावधानों को हटा दिया है। संविधान के अनुच्छेद 35ए को निरस्त कर दिया गया है।
- भारतीय संविधान के सभी प्रावधान अब जम्मू-कश्मीर पर भी लागू हैं।

नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA)

- नागरिकता संशोधन कानून 2014 तक भारत में रह रहे प्रताड़ित अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने का मानवीय कानून है।
- यह कानून पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए वहां के अल्पसंख्यकों पर लागू होगा।
- यह भारत के मुसलमानों सहित किसी भी धर्म के भारतीय नागरिक को प्रभावित नहीं करता है।

समाज के सभी वर्गों के लिए सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना

- मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) विधेयक -2019 पारित कर कानून बनाया गया।
- विवाहित मुस्लिम महिलाओं को वैवाहिक जीवन में (तलाक प्रथा के कारण) असुरक्षा से मुक्ति। मुस्लिम महिलाओं की सामाजिक गरिमा और गौरव में वृद्धि।

राम मन्दिर निर्माण हेतु ट्रस्ट का गठन

माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 09 नवम्बर, 2019 के ऐतिहासिक फैसले के उपरान्त अयोध्या में भव्य राम मन्दिर के निर्माण के लिए श्रीराम जन्म भूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का गठन।

बच्चों को यौन उत्पीड़न/दुराचार से सुरक्षा हेतु कठोर कानून

- पॉक्सो अधिनियम में संशोधन। बाल यौन अपराधियों के लिए मौत की सजा का प्रावधान।
- पॉक्सो से जुड़े मामलों की त्वरित सुनवाई हेतु 1023 फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित करने का निर्णय।
- ट्रांसजेंडर को भेदभाव से बचाने के लिए उनके अधिकारों को परिभाषित किया गया।
- 150 एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों की स्थापना को मंजूरी।

किसानों की आमदनी दोगुनी करने की ओर ठोस कदम

- पी.एम. किसान सम्मान निधि योजना से सभी 14.5 करोड़ किसानों को लाभ।
- पी.एम. किसान मान धन योजना में पहले 03 वर्षों में 5 करोड़ लघु और सीमान्त किसानों को पेंशन का लाभ मिलेगा।
- 60 वर्ष की उम्र पूरी करने वाले किसानों को न्यूनतम रु. 3000 प्रति माह पेंशन।

सरकार का फैसला देश के सुरक्षा प्रहरियों को समर्पित

राष्ट्रीय रक्षा कोष के तहत 'प्रधानमंत्री छात्रवृत्ति योजना' में बड़े बदलाव को मंजूरी

लड़कों के लिए छात्रवृत्ति की राशि को 2000 रुपये प्रतिमाह से बढ़ा कर 2500 रुपये प्रतिमाह किया गया जबकि लड़कियों के लिए 2250 रुपये प्रतिमाह से बढ़ाकर 3000 प्रतिमाह किया गया

छात्रवृत्ति योजना के दायरे को बढ़ाकर राज्यों के पुलिस अधिकारियों के बच्चों को भी इसमें शामिल किया गया

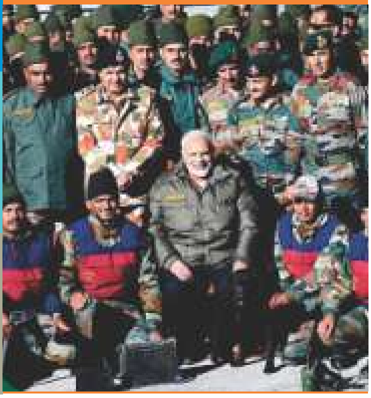

भारत सरकार की महत्वपूर्ण योजनाएं

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना

वर्ष 2022 तक गाँवों के प्रत्येक एकल परिवार को एक स्वच्छ रसोई गैस कनेक्शन उपलब्ध कराने का लक्ष्य। 8 करोड़ 5 लाख परिवारों को गैस कनेक्शन दिया गया। उत्तर प्रदेश में अब तक 1 करोड़ 47 लाख निःशुल्क गैस कनेक्शन वितरित।

प्रधानमंत्री आवास योजना

वर्ष 2022 तक कमजोर और गरीब लोगों को ग्रामीण क्षेत्रों में 3 करोड़ आवास और नगरीय क्षेत्रों में 2 करोड़ आवास देने का लक्ष्य है। अब तक 1 करोड़ 85 लाख आवास निर्मित। उत्तर प्रदेश में 30 लाख से अधिक आवासों का निर्माण/स्वीकृत।

स्वच्छ भारत अभियान

स्वच्छ भारत अभियान के तहत 10 करोड़ 91 लाख व्यक्तिगत शौचालय निर्मित। 6 लाख से ज्यादा ग्राम ओ.डी.एफ. (खुले में शौच से मुक्ति) घोषित।

सौभाग्य योजना

अक्टूबर 2017 से अब तक 2 करोड़ 65 लाख आवासों को निःशुल्क विद्युत कनेक्शन उपलब्ध।

आयुष्मान भारत योजना

1.26 करोड़ गरीब परिवार के करीब 6.47 करोड़ लोगों को 5 लाख रूपये तक का स्वास्थ्य सुरक्षा कवर। अब तक 3.29 लाख लोगों को निःशुल्क उपचार।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना

वर्ष 2014–15 से अब तक 1 लाख 77 हजार किमी. की पक्की सड़कों का निर्माण।

AIIMS (एम्स)/ मेडिकल कॉलेज

22 नये एम्स एवं 75 नये मेडिकल कॉलेज खोलने का निर्णय। वर्ष 2021-22 तक 15,700 अतिरिक्त एम.बी.बी.एस. सीटों में वृद्धि होगी।

स्मार्ट सिटी मिशन

प्रथम चरण में चयनित 100 में से 20 शहर को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के 13 शहर स्मार्ट सिटी मिशन के अन्तर्गत आच्छादित।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना

खरीफ फसल के 2 प्रतिशत तथा रबी फसल के 1.5 प्रतिशत प्रीमियम से वित्तीय सुरक्षा। अब तक 6 करोड़ 18 लाख किसान इस योजना में पंजीकृत।

प्रधानमंत्री ग्राम सिंचाई योजना

योजना के लिए रूपये 50 हजार करोड़ अनुमोदित। इसका उद्देश्य सिंचाई योजनाओं में पूंजी निवेश को आकर्षित करना है।

सांसद आदर्श ग्राम योजना

प्रत्येक संसदीय क्षेत्र के 03 गांवों को सामाजिक-आर्थिक रूप से आदर्श ग्राम के रूप में विकास। वर्ष 2024 में प्रत्येक संसदीय क्षेत्र में 08 गांवों को आदर्श गांव के रूप में विकसित किए जाने का लक्ष्य।

किसान विकास पत्र

कोई भी व्यक्ति केवीपी में निवेश कर सकता है। निवेश की ऊपरी सीमा नहीं है।

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना

योजना में छोटे व्यापार और उद्यम के लिए 50 हजार रु. से 10 लाख रु. तक की पूंजी बैंकों द्वारा ऋण के रूप में उपलब्ध कराई जाती है। अब तक 23 करोड़ 46 लाख उद्यमियों को इस योजना का लाभ। उत्तर प्रदेश के 34 लाख 53 हजार 760 उद्यमी लाभान्वित।

प्रधानमंत्री जीवन-ज्योति योजना

इसके अंतर्गत 330 रूपये के नाम मात्र के अंश दान पर रू0 2 लाख रु. का लाइफ इंश्योरेंस कवर प्राप्त। 6 करोड़ 67 लाख लोग पंजीकृत हुये हैं। उत्तर प्रदेश के 58 लाख 87 हजार 127 लोग लाभान्वित। योजना के क्रियान्वयन में उत्तर प्रदेश का दूसरा स्थान।

प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना

18 से 70 वर्ष के लोगों को मात्र 12 रू. के वार्षिक अंशदान पर 2 लाख रु. का जीवन बीमा कवर। इसके अन्तर्गत 17 करोड़ 85 लाख लोग पंजीकृत।

अटल पेंशन योजना

18 से 40 वर्ष के सभी इच्छुक भारतीयों को 20 वर्षो तक अंशदान से 60 वर्ष की उम्र होने पर अंशदान के अनुसार 1000 से 5000 रु. प्रतिमाह तक की पेंशन। इसके अन्तर्गत 2 करोड़ 12 लाख लोग पंजीकृत। उत्तर प्रदेश के 30 लाख 55 हजार 615 लोग लाभान्वित।

मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना

योजना में 22 करोड़ 32 लाख मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरित। उत्तर प्रदेश में 4 करोड़ से अधिक किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरित।

बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ योजना

योजना में निम्न बाल लिंगानुपात के आधार पर प्रत्येक राज्य में कम से कम एक जिले के साथ 100 जिलों का एक पायलट जिले के रूप में चयन।

जन-औषधि योजना

बाजार मूल्य से कम दाम पर 500 से अधिक दवाओं की बिक्री। अब तक 7 हजार जन-औषधि केन्द्र। उत्तर प्रदेश में प्रथम चरण में 1 हजार जन औषधि केन्द्रों के माध्यम से सस्ती एवं गुणवत्तापूर्ण औषधि उपलब्ध।

मेक इन इण्डिया

मल्टी नेशनल कम्पनियों एवं घरेलू कम्पनियों को अपने सामानों का उत्पादन भारत में करने और रोजगारों के साथ 25 क्षेत्रों में कौशल विकास सुनिश्चित करना इसका मुख्य उद्देश्य है। इसके जरिए भारत में पूंजी और तकनीकी निवेश का माहौल बना है।

कौशल भारत योजना

वर्ष 2022 तक भारत के लगभग 40 करोड़ लोगों को अलग-अलग कौशल में प्रशिक्षित करने का लक्ष्य।

मिशन इंद्रधनुष

इस योजना में 3 करोड़ 65 लाख बच्चों का टीकाकरण।

दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना

योजना के तहत ग्रामीण आवासीय बिजली आपूर्ति और कृषि आपूर्ति के लिए अलग–अलग करते हुए सब–स्टेशन।

दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण योजना

गरीब ग्रामीण युवाओं को नौकरियों में नियमित रूप से न्यूनतम मजदूरी के बराबर या उससे ऊपर मासिक मजदूरी देने का लक्ष्य। ग्रामीण आजीविका को बढ़ावा देने के लिए इस योजना के माध्यम से अब तक 10 लाख युवाओं को प्रशिक्षण।

अमृत योजना

पेयजल आपूर्ति, सीवरेज, नगरीय यातायात उपलब्ध कराते हुए शहरों के गरीबों और वंचितों के जीवन को सुविधाजनक बनाने के लिए देश के 500 शहरों को लिया गया है। **इनमें से 60 शहर उत्तर प्रदेश के हैं।**

स्वदेश दर्शन एवं प्रसाद योजना

'प्रसाद योजना' सभी धर्मों के तीर्थ केन्द्रों पर सुविधाओं और इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार के लिए है। स्वदेश दर्शन योजना विशेष थीम पर आधारित पर्यटन सर्किट के एकीकृत विकास के लिए है।

उड़ान योजना

योजना के माध्यम से मेधावी छात्राओं को स्कूलों से तकनीकी संस्थाओं तक आसानी से जाने तथा गणित और विज्ञान की निःशुल्क ऑनलाइन सुविधा देकर उनको सक्षम बनाने का प्रयास है।

पी.एम. कर्मयोगी मानधन योजना

पी.एम. कर्मयोगी मानधन योजना के तहत 3 करोड़ खुदरा व्यापारियों और दुकानदारों को पेंशन की व्यवस्था।

स्टार्ट अप इण्डिया, स्टैंड-अप इण्डिया

इस महत्वाकांक्षी योजना का उद्देश्य भारत में बिजनेस के सभी क्षेत्रों के नये उद्यमों को प्रोत्साहित करना है। अब तक 28 हजार 815 स्टार्ट अप प्रोजेक्ट्स प्रारम्भ हो चुके हैं।

प्रकाश पथ

स्ट्रीट लाइट में परंपरागत 77 करोड़ बल्बों की जगह एल.ई.डी. बल्ब लगाकर 45 हजार 500 करोड़ रु. मूल्य की 21500 मेगावाट बिजली बचायी गयी है।

पी.एम. श्रम योगी मानधन योजना

असंगठित क्षेत्रों के श्रमिकों को 3000 रु. मासिक पेंशन की सुविधा दिये जाने का प्रावधान। अब तक 40 लाख 62 हजार श्रमिकों का पंजीकरण।

प्रधानमंत्री सुकन्या समृद्धि योजना

इस योजना में कन्याओं के लिए खाते खोलकर 14 साल के लिए जमा राशि संचित होती है। कन्या के 18 साल के होने पर 50 प्रतिशत धनराशि निकाली जा सकती है। 21 वर्ष पूरे होने पर परिपक्वता राशि मय ब्याज (वह राशि जो निष्कासन के समय सरकार द्वारा निर्धारित हो) प्राप्त की जा सकती है। यह राशि कर मुक्त होगी।

गंगा नदी की निर्मलता एवं अविरलता के लिए **'नमामि गंगे'** परियोजना। गंगा की सफाई पर 20 हजार करोड़ रु. की व्यवस्था।

ऊर्जा गंगा

इस योजना के तहत गेल द्वारा 2050 कि.मी. की गैस पाइप लाइन जगदीशपुर (यू.पी.) से हल्दिया (पश्चिम बंगाल) तक बिछायी जायेगी। इसके तहत पूर्वांचल के करीब 20 लाख परिवारों को पी.एन.जी. कनेक्शन मिलेगा।

सौर सुजल योजना

इसके तहत सौर चालित नलकूप किसानों को अनुदानित दरों पर उपलब्ध कराये जा रहे हैं।

प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मान-धन योजना

60 वर्ष की आयु होने पर लघु व्यापारी को 3000 रूपये मासिक न्यूनतम सुनिश्चित पेंशन।

प्रधानमंत्री जन-धन योजना

अत्यंत गरीब लोगों के लिए चलाई गई इस योजना में अब तक 38 करोड़ 6 लाख खाते खोले गये। उत्तर प्रदेश में 6 करोड़ 5 लाख 84 हजार खाते खोले गये। योजना में देश में प्रदेश का प्रथम स्थान है।

देश में अग्रणी...

- तीन वर्षों में 92 हजार 251 करोड़ रुपये का रिकार्ड गन्ना मूल्य भुगतान।
- गन्ना एवं चीनी उत्पादन में देश में लगातार दूसरी बार प्रथम स्थान।
- प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण एवं शहरी) में 30 लाख से अधिक आवास निर्मित/स्वीकृत कर उत्तर प्रदेश देश में प्रथम।
- गेहूं, गन्ना, आलू, हरी मटर, दुग्ध, आम एवं आंवला उत्पादन में प्रथम स्थान।
- स्वच्छ भारत मिशन के अन्तर्गत शौचालय (इज्जतघर) निर्माण में प्रथम स्थान।
- उज्ज्वला योजना के तहत 1.47 करोड़ परिवारों को गैस कनेक्शन देकर देश में प्रथम।
- सौभाग्य योजना में रिकार्ड विद्युत संयोजन के लिए उत्तर प्रदेश पुरस्कृत।
- सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों की स्थापना में प्रथम स्थान।
- जनधन योजना लागू करने में प्रथम स्थान।
- 10 राज्यों में लागू ई–प्रासीक्यूशन प्रणाली के उपयोग में प्रदेश का प्रथम स्थान।
- डी.बी.टी. के माध्यम से किसानों को अनुदान के भुगतान में प्रथम स्थान।
- बी.एल.सी. घटक आवास निर्माण में प्रथम स्थान।
- अटल पेंशन योजना के क्रियान्वयन में देश में प्रथम ।
- उत्तर प्रदेश द्वारा लागू डिजिटल भूमि प्रबन्धन को स्वर्ण पुरस्कार।
- सर्वाधिक खाद्यान्न उत्पादन के लिए 01 करोड़ रुपए का प्रोत्साहन पुरस्कार।
- सर्वाधिक तिलहन उत्पादन के लिए 02 करोड़ रु. का कृषि कर्मण पुरस्कार।
- एक जिला–एक उत्पाद (ओ.डी.ओ.पी.) योजना को मिली राष्ट्रीय पहचान।
- सर्वाधिक चिकित्सा शिक्षण संस्थानों की स्थापना एव संचालन में पूरे देश में अग्रणी।

- सर्वाधिक 126.10 करोड़ लीटर एथनॉल की वार्षिक उत्पादन व आपूर्ति क्षमता।
- मातृ मृत्यु दर में 30 प्रतिशत रिकार्ड गिरावट लाने के लिए एम.एम.आर. अवॉर्ड ।
- मानव वन्य जीव संघर्ष को आपदा घोषित करने वाला उत्तर प्रदेश प्रथम राज्य।
- सड़क व हवाई कनेक्टीविटी में सर्वश्रेष्ठ।
- ईज आफ डूइंग बिजनेस में एचीवर्स श्रेणी में उत्तर प्रदेश आया।
- 'स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण' में सर्वाधिक जन भागीदारी के लिये पुरस्कार।
- औद्योगीकरण के लिये भूमि उपलब्धता व आवंटन में शीर्ष 5 राज्यों में शामिल।
- स्वच्छ सर्वेक्षण–2019 में राष्ट्रीय स्तर पर 14 निकाय सम्मानित।
- सर्वश्रेष्ठ प्राफिट मेकिंग एस.टी.यू. के लिए उत्तर प्रदेश परिवहन निगम को राष्ट्रीय स्तर का पुरस्कार ।
- स्टार्टअप रैकिंग के तहत एस्पायरिंग लीडर के रूप में पुरस्कार।
- वृक्षारोपण महाकुम्भ में 22.59 करोड़ पौधों का रोपण। प्रयागराज में निश्चित अवधि में 76824 निःशुल्क पौध वितरण कर 'गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकार्ड' में नाम दर्ज।
- उत्तर प्रदेश की **'द मिलियन फार्मर्स स्कूल'** योजना को अभिनव प्रयोग मानते हुए इण्टरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट, वॉशिंगटन द्वारा अन्य देशों में लागू करने की अनुशंसा।
- ई–चालान व्यवस्था लागू कर उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य बना।
- माइक्रो एण्ड स्मॉल इण्टरप्राइजेज़ फैसिलिटेशन काउन्सिल का पुरस्कार।
- गणतन्त्र दिवस पर उत्तर प्रदेश की झांकी पुरस्कृत।
- दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग को 05 राष्ट्रीय पुरस्कार।
- पोषण माह में उत्कृष्ट कार्यों के लिए सोशल मीडिया कैटेगरी में सर्वोच्च पुरस्कार ।
- आंगनबाड़ी क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ कार्य के लिए 12 कार्यकर्त्रियाँ राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित।
- ई–मार्केट प्लेस 'जेम' (GeM) पोर्टल में जेम टॉप बायर पुरस्कार।
- कौशल विकास नीति लागू करने वाला पहला राज्य।
- ई–प्रोक्योरमेंट में प्रथम स्थान एवं 'बेस्ट परफार्मिंग स्टेट' पुरस्कार।
- ई–टेण्डरिंग प्रणाली के शत–प्रतिशत कार्यान्वयन हेतु पुरस्कार।
- प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना में 59 लाख लोगों का बीमा कराने का रिकार्ड।
- अयोध्या के दीपोत्सव कार्यक्रम में 05 लाख से अधिक दीप जलाकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकार्ड में नाम दर्ज।

उत्तर प्रदेश का बजट वर्ष 2020-21

मुख्यमंत्री शिक्षुता (Apprenticeship) प्रोत्साहन योजना के क्रियान्वयन से युवाओं को उद्योगों में प्रशिक्षण के साथ–साथ 2500 रुपये का मासिक प्रशिक्षण भत्ता प्रदान किया जाएगा। इसके लिए बजट में 100 करोड़ रुपये की व्यवस्था।

- बजट का आकार 05 लाख 12 हजार 860 करोड़ 72 लाख रुपये। यह बजट अब तक का सबसे बड़ा बजट।
- बजट में 10 हजार 967 करोड़ 87 लाख रुपये की नई योजनाएं सम्मिलित।
- वर्ष 2020–21 का बजट प्रदेश की युवा शक्ति को समर्पित। उन्हें स्वरोजगार तथा रोजगार से जोड़ने के लिये दो महत्वपूर्ण योजनायें–मुख्यमंत्री शिक्षुता (Apprenticeship) प्रोत्साहन योजना तथा युवा उद्यमिता विकास अभियान (YUVA) प्रारम्भ किये जाने का निर्णय।
- युवा उद्यमिता विकास अभियान के तहत प्रत्येक जनपद में 'युवा हब' स्थापित किया जाएगा। यह हब इच्छुक युवाओं को परियोजना, परिकल्पना से लेकर 01 वर्ष तक परियोजनाओं को वित्तीय मदद के साथ संचालन में सहायता करेगा। प्रत्येक जिले में 'युवा हब' की स्थापना हेतु 50 करोड़ रुपये की व्यवस्था।
- प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अन्तर्गत वर्ष 2020–21 में 5 लाख आवासों के निर्माण का लक्ष्य। इसके लिये 6 हजार 240 करोड़ रुपये की व्यवस्था।

- मुख्यमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) हेतु 369 करोड़ रुपये की व्यवस्था।
- स्वच्छ भारत मिशन के अन्तर्गत 5 हजार 791 करोड़ रूपये की व्यवस्था।
- मनरेगा योजना के अन्तर्गत वर्ष 2020–21 में 35 करोड़ मानव दिवस रोजगार सृजन का लक्ष्य। योजना हेतु 4 हजार 800 करोड़ रूपये की व्यवस्था।
- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना हेतु 1 हजार 357 करोड़ रुपये की व्यवस्था।
- ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रमों के अन्तर्गत जल जीवन मिशन हेतु 3 हजार करोड़ रुपये की व्यवस्था।
- बुन्देलखण्ड, विन्ध्य क्षेत्र तथा गुणता प्रभावित ग्रामों में पाईप पेयजल योजना हेतु 3 हजार 300 करोड़ रुपये की व्यवस्था।
- सरयू नहर परियोजना हेतु 1 हजार 554 करोड़ रुपये, मध्य गंगा नहर, द्वितीय चरण हेतु 1 हजार 736 करोड़ रुपये तथा अर्जुन सहायक परियोजना हेतु 252 करोड़ 65 लाख रुपये की व्यवस्था।
- बाढ़ नियंत्रण एवं जल निकासी परियोजनाओं हेतु 966 करोड़ रुपये।
- सबके लिये आवास योजना के अन्तर्गत दुर्बल आय वर्ग के लिये मार्च, 2021 तक 04 लाख भवनों के निर्माण का लक्ष्य।
- नवसृजित जनपदों में 100 शैय्या संयुक्त चिकित्सालयों की स्थापना हेतु 30 करोड रुपये, जिला पुरूष तथा महिला चिकित्सालयों में सुधार–विस्तार एवं नवीनीकरण हेतु 70 करोड़ रुपये, असाध्य रोगों के इलाज हेतु निःशुल्क चिकित्सा सुविधा के लिये 40 करोड़ रुपये, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना हेतु 291 करोड़ रुपये, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी हेतु 919 करोड़ रुपये, एस.जी.पी.जी.आई. हेतु 820 करोड़ रुपये, ग्रामीण आयुर्विज्ञान संस्थान, सैफई हेतु 309 करोड़ रुपये, डॉ0 राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान हेतु 477 करोड़ रुपये, कैंसर संस्थान, लखनऊ के लिये 187 करोड़ रुपये तथा जिला चिकित्सालयों को उच्चीकृत कर मेडिकल कॉलेजों की स्थापना हेतु 73 करोड़ 86 लाख रुपये की व्यवस्था।

- वर्ष 2020–2021 में खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य 641 लाख 74 हजार मीट्रिक टन एवं तिलहन उत्पादन का लक्ष्य 13 लाख 90 हजार मीट्रिक टन निर्धारित। वर्ष 2020–2021 में 61 लाख 43 हजार कुन्तल गुणवत्तापूर्ण बीज तथा 102 लाख मीट्रिक टन उर्वरक वितरण का लक्ष्य।
- प्रदेश के 4 हजार 900 से अधिक गोआश्रय स्थलों में लगभग 04 लाख गोवंश संरक्षित। मुख्यमंत्री सहभागिता योजना के अन्तर्गत 46 हजार से अधिक गोवंश इच्छुक पशुपालकों को सुपुर्द।
- सौर ऊर्जा नीति–2017 के अन्तर्गत वर्ष 2022 तक 10 हजार 700 मेगावॉट क्षमता की सौर विद्युत उत्पादन का लक्ष्य।
- दिल्ली से मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के लिये 900 करोड़ रुपये, आगरा मेट्रो रेल परियोजना हेतु 286 करोड़ रुपये, कानपुर मेट्रो रेल परियोजना हेतु 358 करोड़ रुपये तथा गोरखपुर एवं अन्य शहरों के लिये मेट्रो रेल हेतु प्रस्ताव तैयार किये जा रहे हैं, जिसके लिये 200 करोड़ रुपये की व्यवस्था।
- प्रदेश में पुलिस फोरेन्सिक यूनिवर्सिटी, जनपद प्रयागराज में "लॉ यूनिवर्सिटी" तथा गोरखपुर में आयुष विश्वविद्यालय की स्थापना प्रस्तावित।
- प्रदेश के 18 मण्डलों में अटल आवासीय विद्यालयों की स्थापना हेतु 270 करोड़ रुपये की व्यवस्था।
- स्कूली शिक्षा के उन्नयन हेतु समग्र शिक्षा अभियान के लिए 18 हजार 363 करोड़ रूपये की व्यवस्था।
- 'गंगा एक्सप्रेस–वे' के लिए 2 हजार करोड़ रुपये। जनपद गौतमबुद्ध नगर के जेवर में नोएडा इन्टरनेशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के लिये 2,000 करोड़ रुपये। अयोध्या एयरपोर्ट के लिये 500 करोड़ रुपये।
- ग्रामीण मार्गों के निर्माण, चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु 2 हजार 305 करोड़ रुपये, राज्य सड़क निधि हेतु 1 हजार 500 करोड़ रुपये तथा मार्गों के अनुरक्षण हेतु 3 हजार 524 करोड़ रुपये की व्यवस्था।
- केन्द्रीय मार्ग निधि योजना के अन्तर्गत मार्गों के निर्माण,

चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण को पूर्ण करने हेतु 2 हजार 80 करोड़ रुपये की व्यवस्था।

- पूर्वांचल निधि हेतु 300 करोड़ रुपये तथा बुन्देलखण्ड निधि के लिये 210 करोड़ रुपये की व्यवस्था।
- लखनऊ में राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल की स्थापना हेतु 50 करोड़ रुपये। अयोध्या में उच्च स्तरीय पर्यटक अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु 85 करोड़ रुपये। जनपद वाराणसी में सांस्कृतिक केन्द्र की स्थापना के लिये 180 करोड़ रुपये की व्यवस्था। रामगढ़ ताल, गोरखपुर में वॉटर स्पोर्ट्स के विकास हेतु 25 करोड़ रुपये। श्री काशी विश्वनाथ मन्दिर विस्तारीकरण एवं सौन्दर्यीकरण योजना हेतु 200 करोड़ रुपये की व्यवस्था।
- वृद्धावस्था/किसान पेंशन योजना हेतु 1 हजार 459 करोड़ रुपये, राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना हेतु 1 हजार 251 करोड़ रुपये, दिव्यांग पेंशन योजना हेतु 621 करोड़ रुपये की व्यवस्था।
- मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना हेतु 1 हजार 200 करोड़ रुपये एवं 'मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना' हेतु 250 करोड़ रुपये की व्यवस्था।
- मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना हेतु 500 करोड़ रुपये की व्यवस्था।
- अनुसूचित जाति के छात्र–छात्राओं की छात्रवृत्ति योजनाओं के लिये 2 हजार 35 करोड़ रुपये तथा पिछड़े वर्ग के छात्र–छात्राओं की छात्रवृत्ति योजनाओं के लिए 1 हजार 375 करोड़ रुपये की व्यवस्था।
- प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों में शिक्षा, स्वच्छता, स्वास्थ्य, पेयजल तथा मूलभूत अवस्थापना सुविधाओं में सुधार हेतु 783 करोड़ रुपये की व्यवस्था।
- राज्य आपदा मोचक निधि हेतु 2 हजार 578 करोड़ रुपये तथा राष्ट्रीय आपदा मोचक निधि हेतु 1 हजार करोड़ रुपये की व्यवस्था।

सुरक्षित एवं समरस समाज

- **बेहतर कानून–व्यवस्था के दृष्टिगत लखनऊ एवं नोएडा में पुलिस कमिश्नर व्यवस्था लागू।**
- मा. उच्च न्यायालय, पंजाब एण्ड हरियाणा द्वारा उत्तर प्रदेश की बेहतर कानून–व्यवस्था का विशेष उल्लेख।
- सभी प्रमुख त्योहार, धार्मिक जुलूस, मेले आदि सकुशल सम्पन्न।
- उत्तर प्रदेश पुलिस फॉरेन्सिक यूनिवर्सिटी की स्थापना के लिए 20 करोड़ रुपये की व्यवस्था।
- 10 राज्यों में लागू ई–प्रासीक्यूशन प्रणाली के उपयोग में प्रदेश का प्रथम स्थान।
- कानून–व्यवस्था पर जीरो टालरेन्स की नीति। अपराध और भ्रष्टाचार पर प्रभावी अंकुश। वर्ष 2016 से अबतक का तुलनात्मक विवरण निम्नवत है–

क्र0 सं0	अपराध	वर्ष 2016	वर्ष 2019	वर्ष 2016 के सापेक्ष वर्ष 2019 में अपराधों में कमी का प्रतिशत
1	डकैती	263	106	–59.70 %
2	लूट	4118	2179	–47.09 %
3	हत्या	4679	3663	–21.71 %
4	बलवा	7707	5611	–27.20 %
5	रोडहोल्डप	1	0	–100 %
6	फिरौती के लिए अप0	53	33	–37.74 %
7	दहेज मृत्यु	2439	2375	–2.62 %
8	बलात्कार	3481	2858	–17.90 %

- अपराधों को दर्ज करने हेतु पुलिस अधीक्षक कार्यालयों में एफ.आई.आर. काउन्टर।
- महिलाओं की सुरक्षा हेतु सशक्त वूमेन पावर लाइन–1090
- वूमेन पावर लाइन 1090 को फिक्की द्वारा स्मार्ट पुलिसिंग अवार्ड।
- यू.पी.–100 के रिस्पॉन्स टाइम 45 मिनट की तुलना में यू.पी.–112 नम्बर का रिस्पॉन्स टाइम सुधर कर 10.40 मिनट।
- महिलाओं को त्वरित न्याय के लिए 81 मजिस्ट्रेट स्तरीय न्यायालय एवं 81 अपर सत्र न्यायालय क्रियाशील।
- महिलाओं एवं बालिकाओं के विरुद्ध अपराधों की रोकथाम हेतु पॉक्सो एक्ट। 218 नए फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित ।
- **बुजुर्गों को घर बैठे मदद हेतु 'सवेरा'** कार्यक्रम में 5.25 लाख सीनियर सिटीजंस का रजिस्ट्रेशन।
- 18322 स्कूलों में बालिका सुरक्षा जागरूकता अभियान।
- पुलिस द्वारा अवैध असलहों की बरामदगी बढ़ी। फैक्ट्री निर्मित 343 बन्दूक, 312 पिस्टल, 176 रिवाल्वर, 224 राइफल, 05 ए.के.–47/56, 02 एस.एल.आर., 05 स्टेन/कार्बाइन, 04 हैण्ड ग्रेनेड, 08 बम, 03 टी.एम.सी., 103045 कारतूस, 11345 डेटोनेटर, 540 देशी निर्मित बन्दूक, 51810 पिस्टल, 2082 रिवाल्वर, 417 राइफल, 10 स्टेनगन/कार्बाइन, 460 कारतूस, 3939 बम, 07 टी.एम.सी. तथा 615 शस्त्र फैक्ट्री बरामद।
- आतंकी गतिविधियों एवं अपराधियों पर नियंत्रण हेतु स्पॉट (स्पेशल पुलिस आपरेशन टीम) का गठन।
- सेन्ट्रलाइज्ड ऑनलाइन क्रिमिनल डाटा बेस आइडेन्टीफिकेशन के लिए "त्रिनेत्र" ऐप।
- सोशल मीडिया पर अफवाहों को रोकने के लिए 'डिजिटल वॉलन्टियर' नाम से व्हाट्सएप ग्रुप बनाये गये, जिसमें कुल 6369 एफ.आई.आर. पंजीकृत ।
- सभी कारागारों में सीसीटीवी सर्विलांस इकाईयां स्थापित।
- प्रत्येक जनपद में साइबर सेल का गठन।
- लखनऊ, वाराणसी, आगरा एवं मुरादाबाद में क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला।
- 18 विधि विज्ञान प्रयोगशालाओं के निर्माण का निर्णय। जनपद लखनऊ, वाराणसी, आगरा एवं मुरादाबाद में क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला के भवन निर्मित तथा यूनिट क्रियाशील।
- विधि विज्ञान प्रयोगशालाओं के निर्माण के लिए 60 करोड़ रुपये की व्यवस्था।

अपराधों पर नियंत्रण हेतु नये थाने

क्र.सं.	इकाई	संख्या
1	विद्युत थाने	75
2	महिला थाना	04
3	सतर्कता अधिष्ठान थाना	10
4	आर्थिक अपराध इकाई पुलिस थाना	04
5	घोषणा से आच्छादित थाने	34
6	अन्य स्थापित नवीन थाने	17

जनपद गौतमबुद्धनगर व लखनऊ में साइबर थाने क्रियाशील। 16 परिक्षेत्रीय मुख्यालयों – बरेली, मुरादाबाद, सहारनपुर, आगरा, अलीगढ़, कानपुर, झांसी, प्रयागराज, चित्रकूट, गोरखपुर, देवीपाटन, बस्ती, वाराणसी, आजमगढ़, मिर्जापुर व अयोध्या में साइबर क्राइम पुलिस थाने की स्थापना का निर्णय।

नवीन पुलिस चौकियां एवं अन्य कार्य

क्र.सं.	इकाई	संख्या
1	नवीन पुलिस चौकियां	22
2	जल पुलिस चौकियां (अयोध्या/मिर्जापुर–मां विंध्यवासिनी धाम)	02
3	थानों पर हॉस्टल/बैरक एवं विवेचना कक्ष का निर्माण	322
4	अग्निशमन केन्द्र	66
5	पुलिस प्रशिक्षण संस्थानों में आवासीय/अनावासीय निर्माण	09
6	नवसृजित जनपदों में पुलिस लाइन की स्थापना	07
7	महिला पी0ए0सी0 वाहिनी की स्थापना	03
8	पुलिस लाइन में ट्रांजिट हॉस्टल का निर्माण	44
9	पी0ए0सी0 के लिए 200 व्यक्तियों की क्षमता वाले बैरक का निर्माण	31
10	पुलिस लाइन में महिलाओं एवं पुरुषों हेतु हॉस्टल/बैरक का निर्माण	44

खेतों में हरियाली, किसानों में खुशहाली

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, सहारनपुर में
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का प्रमाण पत्र प्रदान करते हुए।

- **36 हजार करोड़ रु. से 86 लाख लघु एवं सीमांत किसानों का ऋण मोचन।**
- **सभी किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना** का लाभ। अब तक 02 करोड़ 4 लाख किसानों के खाते में कुल 11,718 करोड़ रुपये हस्तांतरित।
- कृषि निवेशों पर देय **रु. 1222 करोड़** की अनुदान धनराशि किसानों के खाते में हस्तांतरित।
- 'द मिलियन फार्मर्स स्कूल' में 54 लाख से अधिक किसानों को नवीनतम तकनीक में प्रशिक्षण।
- 17 लाख किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड के अन्तर्गत 13 हजार 600 करोड़ के ऋण की व्यवस्था से कृषि निवेश में भारी वृद्धि।

खाद्यान्न एवं तिलहन उत्पादन

- **खरीफ 2019 में 209.88 लाख मी.टन खाद्यान्न एवं 1.65 लाख मी.टन तिलहन उत्पादन। रबी 2019–20 में 415.25 लाख मी.टन खाद्यान्न एवं 10.11 लाख मी.टन तिलहन का उत्पादन अनुमानित।**

धान खरीद

क्र0 सं0	धान क्रय वर्ष	लक्ष्य (लाख मी0 टन में)	खरीद (लाख मी0 टन में)	लाभान्वित कृषक
1	2017–18	50.00	42.90	4,92,038
2	2018–19	50.00	48.25	6,84,013
3	2019–20	50.00	53.47	6,62,786

गेहूँ खरीद

क्र0सं0	क्रय वर्ष	लक्ष्य (लाख मी0 टन में)	खरीद (लाख मी0 टन में)	लाभान्वित कृषक
1	2017–18	40.00	36.99	8,00,646
2	2018–19	50.00	52.92	11,27,195
3	2019–20	55.00	37.04	7,53,414

तिलहन खरीद

क्र0सं0	क्रय वर्ष	खरीद (लाख मी0 टन में) सरसों, राई, मूंगफली
1	2018–19	9579
2	2019–20	1455.75

दलहन खरीद

क्र0सं0	क्रय वर्ष	खरीद (लाख मी0 टन में)
1	2017–18	23,000
2	2018–19	28,096
3	2019–20	906.25

- **2 लाख 49 हजार 445 करोड़ रुपए** का फसल ऋण वितरित।
- **4 करोड़ से अधिक मृदा स्वास्थ्य कार्ड** एवं **1.11 करोड़ किसान क्रेडिट कार्ड** वितरित।
- **20 कृषि विज्ञान केन्द्रों** की स्थापना।
- **प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना** में 2 लाख 39 हजार 050 लाभार्थियों को कार्ड उपलब्ध कराये गये।
- **प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना** के अन्तर्गत खरीफ 2018 में 5.69 लाख किसानों को 434.27 करोड़ रुपये, रबी 2018–19 में 0.39 लाख किसानों को 18.39 करोड़ रुपये, खरीफ 2019 में 1.35 लाख किसानों को 55.02 करोड़ रु. की क्षतिपूर्ति।
- रबी 2019–20 में 19.91 लाख बीमित किसानों की 15 लाख हे. फसलों का बीमा।
- **फसली ऋण के अन्तर्गत**

- खरीफ 2019 में 38298.17 करोड़ रु.।
- रबी 2019–20 में माह नवम्बर 2019 तक 17190.20 करोड़ रु.।

- **राष्ट्रीय कृषि बाजार योजना** के तहत 100 मण्डियों के माध्यम से इस वर्ष 148380.11 लाख रु. का व्यापार।
- 251 मण्डी स्थल निर्मित।
- मण्डी परिषद की आय में अभूतपूर्व वृद्धि। वर्ष 2016–17 में मण्डी परिषद की आय 1210 करोड़ रु. थी, जो वर्ष 2018–19 में बढ़कर 1822 करोड़ रु. हो गयी। 2019–20 में माह जनवरी, 2020 तक कुल 1700 करोड़ रु. की आय प्राप्त, जो गत वर्षों की समान अवधि के सापेक्ष 703 करोड़ रु. अधिक।
- प्रदेश की 27 मण्डियों का आधुनिकीकरण।
- **मुख्यमंत्री कृषक कल्याणकारी योजना** के अन्तर्गत 53 हजार 097 किसानों को 77 हजार करोड़ सहायता राशि दी गयी।
- **'मुख्यमंत्री कृषि उत्पादन मण्डी समिति के व्यापारी एवं आढ़ती दुर्घटना सहायता योजना' एवं 'मुख्यमंत्री मण्डी स्थल/ उप मण्डी स्थल अग्नि दुर्घटना सहायता योजना' लागू।**

गन्ना किसानों को सुविधाएं

- गन्ना एवं चीनी उत्पादन में **उत्तर प्रदेश** का **देश में प्रथम स्थान।**
- किसानों को **92 हजार 251 करोड़ रु.** गन्ना मूल्य का रिकार्ड भुगतान।
- मुण्डेरवा, पिपराइच एवं रमाला चीनी मिलों का विस्तार एवं पेराई क्षमता में वृद्धि। 11 चीनी मिलों की क्षमता में विस्तार।
- पूर्व स्थापित खाण्डसारी इकाइयों के पुनर्संचालन हेतु निःशुल्क लाइसेंस नवीनीकरण।
- 25 वर्ष में पहली बार 105 नई खाण्डसारी इकाइयों के लाइसेंस स्वीकृत, जिससे 27850 टी.सी.डी. की अतिरिक्त पेराई क्षमता सृजित।

एथेनॉल उत्पादन :–

- उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा एथेनॉल आपूर्तिकर्ता बना।

भरपूर सिंचाई, फसल लहलहाई

46 वर्षों से लंबित बाण सागर परियोजना सहित पहाड़ी बांध परियोजना, पथरई बांध परियोजना, जमरार बांध परियोजना, मौदहा बांध परियोजना, पहुॅज बांध परियोजना, लहचुरा बांध और गुण्टा बांध सहित 8 परियोजनाएं पूर्ण। इन परियोजनाओं के पूर्ण होने से **2 लाख 16 हजार हेक्टेयर सिंचन क्षमता में वृद्धि।**

मार्च 2020 तक निम्नलिखित सिंचाई परियोजनाओं पूर्ण करने का लक्ष्य।

क्र0सं0	परियोजना का नाम	लाभान्वित जनपद	पूर्ण होने का वर्ष	प्रस्तावित सिंचन क्षमता (हे0)	परियोजना पूर्ण होने पर लाभान्वित कृषक	अद्यतन प्रगति
1	सरयू नहर परियोजना	बहराइच, गोण्डा, बलरामपुर, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर, सन्तकबीरनगर, बस्ती, गोरखपुर एवं महराजगंज	2020–21	14.04 लाख	29.74 लाख	81 %
2	अर्जुन सहायक परियोजना	महोबा, हमीरपुर एवं बांदा	2020–21	44381	1.49 लाख	90 %
3	मध्य गंगा नहर परियोजना	अमरोहा, सम्भल एवं मुरादाबाद	2020–21	1.46 लाख	3.91 लाख	55 %
4	भावनी बांध परियोजना	ललितपुर	2019–20	3800	2250	90 %
5	रसिन बांध परियोजना	चित्रकूट	2019–20	2290	3625	95 %
6	बण्डई बांध परियोजना	ललितपुर	2019–20	3025	1700	95 %

7	मसगांव एवं चिल्ली स्प्रिंकलर सिंचाई परियोजना	हमीरपुर	2019–20	600	200	90 %
8	जाखलौन नहर	ललितपुर	2019–20	1496	1392	98 %
9	लखेरी बांध परियोजना	झांसी	2020–21	3098	3240	93 %
10	रतौली वीयर परियोजना	महोबा	2020–21	650	529	81 %
11	कुलपहाड़ स्प्रिंकलर सिंचाई परियोजना	महोबा	2020–21	1700	1100	64 %
12	शहजाद बांध स्प्रिंकलर सिंचाई परियोजना	ललितपुर	2020–21	1740	1500	64 %

उपरोक्त परियोजनाओं के पूर्ण होने से 16.15 लाख हे. सिंचन क्षमता में वृद्धि होगी एवं 5.92 मेगावाट प्रदूषण विहीन ऊर्जा (विद्युत) का उत्पादन होगा।

वित्तीय वर्ष 2020–21 में कचनौदा बांध परियोजना, भौरट बांध परियोजना, उमरहट पम्प नहर परियोजना एवं उत्तर प्रदेश वाटर सेक्टर रीस्ट्रक्चरिंग परियोजना पूर्ण करने का लक्ष्य है। इन परियोजनाओं के पूर्ण होने से कुल 2.056 लाख हे. सिंचन क्षमता सृजित होगी।

- बुन्देलखण्ड में 8384 खेत तालाबों का निर्माण।
- 3869 किमी. लम्बाई के 523 तटबन्धों पर बाढ़ सुरक्षात्मक कार्य पूर्ण।
- बाढ़ सुरक्षा की 149 परियोजनाएं पूर्ण।
- 50 लाख किसान ड्रिप स्प्रिंकलर सिंचाई योजना से लाभान्वित।
- 2,97,477 निःशुल्क बोरिंग करते हुए 1 लाख 61 हजार 85 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचन क्षमता में वृद्धि।
- 15800 सोलर पम्प की स्थापना का कार्य प्रगति पर।

सिल्ट सफाई का विवरण

वित्तीय वर्ष	धनराशि (करोड़ रु. में)	खरीफ लम्बाई (कि.मी.)	रबी लम्बाई (कि.मी.)	योग लम्बाई (कि.मी.)
2017–18	100	7371	18027	25398
2018–19	100	535	26899	27434
2019–20	173	835	45166	46001

नहरों से सींच का विवरण

(आंकड़े हजार हे. में)

क्र. सं.	फसली वर्ष	खरीफ	रबी
1	2017–18	3537.32	4717.30
2	2018–19	3660.12	4950.21
3	2019–20 (अब तक)	3858.28	2126

- 2,97,477 निःशुल्क बोरिंग, 2,615 गहरी बोरिंग बोरिंग, 9,580 मध्यम गहरी बोरिंग की गई।
- **'हर घर नल योजना'** से पिछड़े इलाकों में शुद्ध पेयजल की व्यवस्था।
- बुंदेलखंड जैसे सूखा प्रभावित इलाके में **'घर–घर पेयजल'** की व्यवस्था।
- कानपुर से 18 करोड़ लीटर गंदा पानी रोज गंगा में गिर रहा था, लेकिन अब 95 परसेंट पानी ट्रीट होकर गंगा में गिर रहा है। एशिया का 128 साल पुराना सीसामऊ नाला अब पूरी तरह से टैप होने से गंगा में जल गुणवत्ता बढ़ी।
- 2000 नवीन राजकीय नलकूपों का निर्माण कर 69050 हे. सिंचन क्षमता का सृजन कर 67600 कृषक परिवार लाभान्वित।
- बुन्देलखण्ड में 60 असफल राजकीय नलकूपों को पुनर्निर्मित कर 6000 हेक्टेयर सिंचन क्षमता की पुनर्स्थापना।
- अन्य क्षेत्रों में असफल 40 राजकीय नलकूपों को पुनर्जीवित कर 4 हजार हे. सिंचन क्षमता की पुनर्स्थापना।
- अदसड़ न्यू नहर परियोजना (चन्दौली), घूरियाघाट पम्प नहर परियोजना (मिर्जापुर) एवं देउम पम्प नहर परियोजना (प्रतापगढ़) को पूर्ण करने का लक्ष्य। इन परियोजनाओं को पूर्ण होने से 6019 हेक्टेयर सिंचन क्षमता सृजित होगी।

नमामि गंगे यात्रा

27-31 जनवरी, 2020

भगीरथ प्रयास

27 जिले | 21 नगर निकाय
1038 ग्राम पंचायत | 1358 किमी.

बिजनौर से कानपुर | बलिया से कानपुर

लगभग 7 करोड़ 83 लाख लोगों से जनसम्पर्क कर निर्मल एवं अविरल गंगा के प्रति जागरूक किया गया।

नमामि गंगे यात्रा के दौरान किये गये कार्यों का विवरण

- 33,979 आयुष्मान कार्ड्स का वितरण।
- 1,13,881 राशन कार्ड्स का वितरण।
- 1,07,309 परिवारों को मनरेगा के तहत रोजगार।
- 1,652 स्थान गंगा नर्सरी/वृक्षारोपण हेतु चिन्हित।
- 2,646 स्वास्थ्य मेलों का आयोजन।
- 943 ग्रामों में पशु मेलों का आयोजन।
- 88 शवदाह गृहों का निर्माण कार्य प्रारम्भ।
- आजीविका मिशन के अन्तर्गत 6,952 लोग लाभान्वित।
- ग्रामोद्योग योजना के अन्तर्गत 61 लोग लाभान्वित।
- 31,897 कृषकों को जीरो बजट/आर्गेनिक खेती का प्रशिक्षण।
- 26,831 प्रधानमंत्री आवास एवं 1,039 मुख्यमंत्री आवासों का आवंटन।
- 1,16,671 नवीन शौचालयों का निर्माण कार्य प्रारम्भ।
- सौभाग्य योजना के अन्तर्गत 7,605 विद्युत कनेक्शन का वितरण।
- विधवा पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन एवं दिव्यांगजन पेंशन योजना के अन्तर्गत 15,993 लाभार्थियों को पेंशन वितरण।
- 512 गंगा तालाबों, 654 गंगा आरती चबूतरों, 381 गंगा मैदानों, 118 गंगा पार्कों एवं 1,292 गंगा उद्यानों का निर्माण कार्य प्रारम्भ।
- पर्यावरण संरक्षण एवं पॉलीथीन मुक्ति के प्रति जन-जागरूकता।
- खेल प्रतियोगिताओं एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से माँ गंगा की महिमा एवं जनकल्याणकारी योजनाओं का प्रचार।

पारदर्शी खाद्यान्न वितरण

- उज्ज्वला योजना के अंतर्गत 1.47 करोड़ से अधिक निःशुल्क गैस कनेक्शन वितरित।
- राशनकार्ड पोर्टेबिलिटी प्रदेश के नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में लागू।
- नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्र की समस्त उचित दर की दुकानों में ई–पॉस माध्यम से लाभार्थियों को खाद्यान्न वितरण।
- समस्त 80298 उचित दर की राशन की दुकानों का डाटा डिजिटलीकरण।
- अन्त्योदय योजना में 40 लाख 94 हजार 500 राशनकार्डों तथा समस्त चयनित पात्र गृहस्थी के 3 करोड़ 11 लाख 64 हजार 304 कार्डधारकों का डाटा डिजिटाईज।
- खाद्यान्न के आवंटन, गोदामों से उठान एवं वितरण की ऑनलाइन फीडिंग कराकर मॉनीटरिंग।
- गेहूँ का न्यूनतम समर्थन मूल्य 1925 रुपये प्रति कुन्तल निर्धारित।
- रबी वर्ष 2019–20 के दौरान गेहूँ खरीद के लिए 6796 क्रय केन्द्रों पर कुल 37.04 लाख मी.टन रिकार्ड गेहूँ खरीद।
- 7 लाख 53 हजार 414 किसानों से गेहूँ क्रय करते हुए 6889.15 करोड़ रुपये का भुगतान सीधे किसानों के खातों में किया गया।
- ग्रेड–ए धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य रु. 1835 प्रति कुन्तल तथा कामन धान का मूल्य रु. 1815 प्रति कुन्तल निर्धारित। 20 रुपये प्रति कुन्तल कृषकों को उतराई छनाई हेतु अतिरिक्त दिया जा रहा है।
- 3977 क्रय केन्द्रों पर फरवरी, 2020 तक 55.53 लाख मीट्रिक टन धान क्रय कर 6 लाख 89 हजार 767 किसानों को 10158.85 करोड़ रु. का भुगतान ।
- मक्के के लिए 1760 रु. प्रति कुन्तल न्यूनतम मूल्य निर्धारित किया गया।
- 23 जनपदों के 100 क्रय केन्द्रों पर 25.13 मीट्रिक टन मक्के की खरीद करते हुए 50340 किसानों को भुगतान किया जा चुका है। 20 रुपये प्रति कुन्तल कृषकों को उतराई छनाई हेतु अतिरिक्त।

गाँव-गाँव विकास की बयार

- प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) में 13 लाख 75 हजार आवास निर्मित। 63 हजार 237 आवासों का निर्माण कार्य प्रगति पर।
- ग्रामीण क्षेत्रों में 2 करोड़ 61 लाख परिवार शौचालयों से आच्छादित।
- मुसहर, कोल, थारू एवं वनटांगिया समुदाय के 38 ग्रामों को राजस्व ग्राम घोषित करते हुए आवास, चिकित्सा, शिक्षा, सड़क, बिजली एवं राशन कार्ड आदि मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करायी गयी।
- मुख्यमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) में 50740 निःशुल्क आवास दिए गए। इनमें से 27764 आवास मुसहर, 4666 आवास वनटांगिया, 81 आवास थारू जनजाति के व्यक्तियों तथा शेष अन्य पात्र व्यक्तियों को दिए गए।
- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत 9109 किमी0 सड़कों का निर्माण, 38652 किमी. सड़कों की गड्ढामुक्ति एवं 1432 किमी. सड़कों का पीरियाडिक रिन्यूवल किया गया।
- वेस्ट प्लास्टिक, कोल्ड मिक्स, नैनो टेक्नोलोजी, सीसी ब्लाक आदि नई तकनीक से 29.72 किमी0 सड़कें निर्मित एवं 154.78 किमी का कार्य प्रगति पर।
- पीएमजीएसवाई–3 के अन्तर्गत 18937.05 किमी0 का लक्ष्य।
- मनरेगा के अन्तर्गत 63 करोड़ लक्षित मानव दिवस के सापेक्ष 61.09 करोड़ मानव दिवस सृजित।
- मनरेगा के अन्तर्गत प्रदेश की 25 नदियों का पुनरुद्धार।
- मनरेगा के तहत 14.82 करोड़ पौधों का रोपण।
- विगत तीन वर्षों में 46 हजार 996 तालाबों का निर्माण ।
- मनरेगा के माध्यम से प्रदेश में अब तक 13,433 आंगनवाड़ी केन्द्रों का निर्माण।
- ग्रामीण अवस्थापना के विभिन्न कार्यों हेतु विगत तीन वर्षों में 5676 करोड़ रु. व्यय किये गये।
- उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन 52 जनपदों के 453 विकास खण्डों में लागू।

ग्रामीण आजीविका मिशन की भौतिक प्रगति का विवरण

क्र.स.	घटक	वित्तीय वर्ष 2017–18	वित्तीय वर्ष 2018–19	वित्तीय वर्ष 2019–20 (अब तक)
1	समूह का गठन	49372	65157	93308
2	रिवाल्विंग फण्ड	37223	39938	49558
3	बैंक क्रेडिट	18152	25305	24550
4	सी0आई0एफ0	12764	30558	36978
5	ग्राम संगठन	2884	3453	4698
6	क्लस्टर लेवल फेडरेशन	157	137	137

शिक्षा का बढ़ा दायरा

बेसिक शिक्षा

- 'स्कूल चलो अभियान' के अन्तर्गत तीन सालों में 4 करोड़ 71 लाख से अधिक बच्चों का नामांकन।
- सरकारी स्कूलों में बच्चों को पहली बार स्वेटर एवं जूता–मोजा का वितरण।
- प्राथमिक विद्यालयों में 45,383 अध्यापकों की भर्ती पूर्ण, 69 हजार की भर्ती प्रक्रिया अन्तिम चरण में।
- दुर्बल वर्ग के बच्चों के विद्यालय नामांकन एवं प्रवेश के लिए 202 करोड़ रु. का प्रावधान।
- 'आउट ऑफ स्कूल' बच्चों के चिन्हांकन एवं नामांकन हेतु शारदा 'स्कूल हर दिन आएं' कार्यक्रम।
- विद्यालयों में ब्लैक बोर्ड, शौचालय, पेयजल, हैण्ड वाश, विद्युतीकरण, फर्श की मरम्मत, किचन शेड के लिए ऑपरेशन कायाकल्प योजना संचालित।
- 15 हजार परिषदीय विद्यालय में अंग्रेजी माध्यम से शिक्षण कार्य संचालन।
- दिव्यांग बच्चों को तकनीकी सपोर्ट के लिए मोबाईल ऐप आधारित इन्टीग्रेटेड प्रणाली (समर्थ) संचालित।
- 731 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय निर्मित एवं 13 विद्यालयों का निर्माण कार्य प्रगति पर।
- राज्य अध्यापक पुरस्कार की धनराशि 10,000 रु. से बढ़ाकर 25,000 रु. की गयी।

माध्यमिक शिक्षा

- अध्यापकों के 5 हजार 987 नवीन पदों का सृजन।
- 193 नये इण्टर कालेज संचालित एवं 55 नये इण्टर कालेज की स्वीकृति।
- शुल्क विनियमन अधिनियम लागू।
- सेवा सम्बन्धी विवाद निस्तारण के लिए शिक्षा सेवा अधिकरण की व्यवस्था।
- उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की स्थापना।
- व्यावसायिक शिक्षा पाठ्यक्रम में 5 नये ट्रेड शामिल।
- यू.पी. बोर्ड में नकलविहीन परीक्षाएं।
- एन.सी.ई.आर.टी. पाठ्यक्रम लागू।
- समस्त राजकीय इण्टर कालेजों में सह–शिक्षा की व्यवस्था।
- शैक्षिक दृष्टि से पिछडे 30 विकास खण्डों में बालिका छात्रावास संचालित।
- शैक्षिक दृष्टि से 107 विकास खण्डों में बालिका छात्रावास निर्माणाधीन।

- श्रमिकों के बच्चों के लिए सभी 18 मण्डलों में अटल आवास विद्यालय की स्थापना।
- यू.पी. बोर्ड के मेधावी विद्यार्थियों के निज ग्राम तक गौरव पथ का निर्माण।

उच्च शिक्षा

- बालिकाओं को स्नातक तक निःशुल्क शिक्षा।
- जनपद सहारनपुर, आजमगढ़ एवं अलीगढ़ में 3 राज्य विश्वविद्यालयों की स्थापना हेतु भूमि–बजट की व्यवस्था।
- पं. दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में महायोगी गुरु श्री गोरक्षनाथ शोध पीठ की स्थापना।
- प्रो. राजेन्द्र सिंह (रज्जू भैया) के नाम पर पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर में रिसर्च सेंटर की स्थापना।
- पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर डी0ए0वी0 कालेज, कानपुर में सेन्टर ऑफ एक्सीलेन्स की स्थापना।
- 49 नये राजकीय महाविद्यालयों की स्थापना–कार्य प्रगति पर।
- 25 मॉडल राजकीय महाविद्यालयों की स्थापना कार्य गतिमान और 1 मॉडल राजकीय महाविद्यालय संचालित।
- 24 राजकीय पॉलीटेक्निक तथा प्राविधिक शिक्षा, 4 राजकीय इंजीनियरिंग कालेज की स्थापना।
- प्रदेश में 147 राजकीय पॉलीटेक्निक संचालित। 26 नवीन पॉलीटेक्निक संस्थानों का निर्माण शुरू।

व्यावसायिक शिक्षा

- राजकीय आई.टी.आई की संख्या 260 से बढ़ाकर 305 की गयी।
- प्रदेश में राजकीय आई.टी.आई में 1 लाख 72 हजार सीटें उपलब्ध।
- 34 असेवित क्षेत्रों में नये राजकीय आई.टी. आई. की स्थापना की कार्यवाही।

कौशल विकास से रोज़गार

स्टार्ट-अप, स्टैण्ड अप संस्कृति को बढ़ावा

- प्रदेश में **स्टार्ट–अप** संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए 13 इन्क्यूबेटर्स कार्यरत।
- **प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, स्टैण्ड–अप इण्डिया योजना, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना एवं प्रधानमंत्री रोजगार सृजन** कार्यक्रम में 18 हजार 490 रोजगार सृजित।

कौशल विकास से मिला रोजगार

- समन्वित कौशल विकास नीति प्रख्यापित करने में देश में प्रथम राज्य।
- सभी असेवित तहसीलों में 79 कौशल विकास प्रशिक्षण केन्द्र तथा 59 जिलों में प्रधानमंत्री कौशल विकास केन्द्र खोले गए।
- कौशल विकास प्रशिक्षण हेतु पंजीकरण से लेकर प्रशिक्षण व सेवायोजन की पूर्णतः पारदर्शी एवं ऑनलाइन प्रक्रिया प्रारम्भ।
- 10 लाख से अधिक युवाओं का पंजीकरण, 8.48 लाख से अधिक युवा प्रशिक्षित तथा 3 लाख से अधिक युवा सेवायोजित।
- एसौचैम द्वारा कौशल विकास में सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में **स्वर्ण ट्राफी।**
- **मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार** योजनान्तर्गत उद्योग स्थापना हेतु रु. 25.00 लाख तक एवं सेवा क्षेत्र हेतु रु. 10.00 लाख तक के ऋण की व्यवस्था।

राजस्व : बढ़ी पारदर्शिता

भू–माफियाओं तथा अतिक्रमणकर्ताओं के विरुद्ध कार्रवाई

- राज्य, मण्डल, जनपद, व तहसील स्तर पर एंटी भू–माफिया टास्क फोर्स का गठन।
- **टास्क फोर्स द्वारा कार्रवाई का विवरणः–**

कार्रवाई की स्थिति (तीन वर्षों में)	योग
अवैध अतिक्रमण से अवमुक्त कराया गया क्षेत्रफल (हे0)	68851
दर्ज कराये गये राजस्व वाद	22547
दर्ज कराये गये सिविल वाद	820
दर्ज करायी गयी एफ0आई0आर0	3887

- अब तक 48 लाख 13 हजार 140 राजस्व वादों का निस्तारण।
- **अविवादित वरासत** : प्रकरणों का समयबद्ध निस्तारण करने हेतु आनलाईन पोर्टल। अब किसी भी कृषक की मृत्यु पर उसके वारिसों द्वारा कहीं से भी आनलाइन वरासत अंकित करने के लिए प्रार्थना पत्र दिया जा सकता है, जिसका निस्तारण एक माह में करना अनिवार्य है। यदि राजस्व निरीक्षक की जांच में वरासत विवादित पायी जाती हैं तो सम्बन्धित न्यायालय में स्वतः वाद पंजीकृत करके कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जाएगी।
- **हैसियत प्रमाण–पत्र** के लिए भी आवेदन आनलाईन, 30 दिन के अन्दर जिला प्रशासन को निस्तारण करना अनिवार्य।
- **सह खातेदारों के अंश निर्धारण** हेतु अभियान।
- कुल 51 हजार 324 ग्रामों के सहखातेदारों का अंश निर्धारित।
- ग्राम समाज की कृषि भूमि 26,149 भूमिहीनों के मध्य 5692.86 हे. भूमि वितरित।
- आवास स्थल 62023 परिवारों को 577 हे0 भूमि वितरित।
- 17833 मछुआरों को 19275.63 हे0 तालाबों का आवंटन।

- कुम्हारी कला : 7438 कलाकारों को 6155 हे0 स्थल आवंटित।
- वृक्षारोपण के लिए 5564 लोगों को 1854. 207 हे0 भूमि आवंटित।

प्रक्रिया का सरलीकरण

- **औद्योगीकरण** हेतु कृषि भूमि को गैर–कृषक भूमि घोषित कराने के लिए नियमों को शिथिल करते हुए 05 वर्ष के सम्भावित भू–उपयोग को देखते हुए कृषक से गैर–कृषक भूमि घोषित करने का प्रावधान।
- 12.5 एकड़ से अधिक गैर कृषक भूमि क्रय करने हेतु शासन से अनुमति को सरल करते हुए 50 एकड़ तक जिलाधिकारी, 100 एकड़ तक मण्डलायुक्त को शासन की शक्तियां प्रतिनिधानित। 100 एकड़ से अधिक भूमि क्रय करने हेतु पूर्व की भांति शासन के अनुमति की आवश्यकता होगी।
- प्रदेश में निजी भूमि को पट्टे पर देने के लिए नियमों में शिथिलता। कोई खातेदार कृषि कार्य के लिए 15 वर्ष तक अपनी भूमि को पट्टे पर दे सकता है एवं सौर ऊर्जा के लिए 30 वर्ष हेतु भूमि पट्टे पर दे सकता है।
- **गाटों का यूनीक कोड :** समस्त गाटों को एक यूनिक कोड प्रदान करते हुए भूलेख पोर्टल (खतौनी) को निबंधन विभाग, राजस्व न्यायालय कम्प्यूटरीकृत प्रबन्धन प्रणाली एवं भू–नक्शा पोर्टल से लिंक कर दिया गया है, जिससे कोई भी खातेदार कहीं से भी एक क्लिक पर भूमि के बन्धक, राजस्व न्यायालय में विवादित/वादग्रस्त होने या उसके विक्रीत होने की स्थिति को जान सकता है।

महिलाओं को समान अधिकार

- महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार प्रदान करने के उद्देश्य से राजस्व संहिता में पौत्री (पुत्र की पुत्री,) भतीजी (सगे भाई की पुत्री) और भांजियों (सगी बहन की पुत्री) को भी भौमिक अधिकार दिये जाने का प्रावधान।

स्मार्टफोन/लैपटॉप

- शासकीय कार्य की सुगमता हेतु समस्त लेखपालों/राजस्व निरीक्षकों को स्मार्ट फोन एवं लैपटाप उपलब्ध कराये जा रहे हैं।

आपदा प्रबन्धन

- शीतलहर के दौरान गरीब, असहाय एवं निराश्रित परिवारों/ लोगों के लिए कम्बल वितरण एवं अलाव की व्यवस्था।

वर्ष	2017–18	2018–19	2019–20 (दिनांक 27.01.2019 तक)
वितरित कम्बल	737675	717090	10,51,940
संचालित रैन बसेरे	1153	863	1006
अलाव	84707	159056	450298

तीन वर्षों में 670 राहत कैम्प लगाकर 23 लाख 16 हजार 156 बाढ़ प्रभावित परिवारों को फूड पैकेट वितरित।

सुविधाएं बढ़ीं : सेहत सुधरी

- **आयुष्मान योजना** में 1 करोड़ 18 लाख गरीब परिवारों को 5 लाख रु. का चिकित्सा बीमा कवर। 2554 निजी एवं सरकारी चिकित्सालय सूचीबद्ध। 90 लाख 22 हजार 145 गोल्डेन कार्ड्स बने।
- 10 लाख 56 हजार छूटे हुए परिवार **'मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना'** से आच्छादन हेतु लक्षित।
- प्रत्येक रविवार को प्रदेश के सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर **मुख्यमंत्री आरोग्य मेला** का आयोजन।
- **जे.ई./ए.ई.एस. की रोकथाम हेतु प्रभावी प्रयास से इंसेफ्लाइटिस के मामलों में 75 प्रतिशत एवं मृत्यु के आंकड़ों में 90 प्रतिशत की कमी।**
- विशेष संचारी रोग, दिमागी बुखार के कारण होने वाली मृत्यु दर में भारी कमी। जे0ई0/ए0ई0एस0 रोग से बचाव के लिए विशेष अभियान चलाकर टीकाकरण।

प्रत्येक रविवार को प्रदेश के सभी पी.एच.सी. पर मुख्यमंत्री आरोग्य मेले का आयोजन। अब तक चार आरोग्य मेलों में 21.99 लाख से अधिक लोगों का उपचार। 66,494 हजार से अधिक गम्भीर रोगी बड़े अस्पतालों के लिए रेफर। इन मेलों में आयुष्मान भारत योजना के तहत 1 लाख 66 हजार 459 गोल्डन कार्ड वितरित।

वर्ष	ए.ई.एस.			पुष्ट जे.ई.		
	कुल रोगी	कुल मृतक	रोग मृत्यु दर	पुष्ट जे.ई.	मृतक	रोग मृत्यु दर
2017	4724	655	13.87%	693	93	13.42%
2018	3077	248	8.06%	329	30	9.12%
2019	2185	126	5.77%	235	21	8.94%

- **अटल बिहारी बाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय लखनऊ** का शिलान्यास।
- **गोरखपुर एवं रायबरेली में एम्स की स्थापना।**
- **गोरखपुर में आयुष विश्वविद्यालय की स्थापना प्रक्रियाधीन।**
- रोटा वायरस वैक्सीन एवं मीजिल्स रूबेला वैक्सीन को नियमित टीकाकरण में शामिल करते हुए 7 करोड़ 57 लाख बच्चों का टीकाकरण।
- **7 नये मेडिकल कॉलेज** में पढ़ाई प्रारम्भ। शैक्षणिक सत्र 2019–20 में एम.बी.बी.एस. की सीटों में 700 की वृद्धि। प्रथम चरण में **05 जिला चिकित्सालयों** (अयोध्या, बहराइच, बस्ती, फिरोजाबाद एवं शाहजहांपुर) को उच्चीकृत कर मेडिकल कॉलेज बनाया गया। इसके अतिरिक्त बदायूं एवं ग्रेटर नोएडा में एम.बी.बी.एस. पढ़ाई प्रारम्भ। एटा, हरदोई, प्रतापगढ़, फतेहपुर, सिद्धार्थनगर, देवरिया, गाजीपुर एवं मिर्जापुर में **8 नये मेडिकल कॉलेज** का निर्माण कार्य प्रगति पर।
- **13 नये मेडिकल कॉलेज** की स्थापना की स्वीकृति।
- 250 एडवांस लाइफ सपोर्ट सेवाएं संचालित।
- 102 व 108 एम्बुलेंस सेवा के तहत 4470 एम्बुलेंस संचालित।
- प्रदेश में 853 सी.एच.सी. तथा 3620 पी.एच.सी. संचालित। 80 नये पी.एच.सी. निर्माणाधीन तथा 105 नये सी.एच.सी. स्वीकृत।
- दिसम्बर 2019 तक 593 हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर क्रियाशील।
- **'मिशन इन्द्रधनुष'** के तहत शत– प्रतिशत बच्चों का प्रतिरक्षण।
- **प्रधानमंत्री जन औषधि केन्द्र योजना** के अन्तर्गत प्रदेश के 1000 जन औषधि केन्द्रों में सस्ती दर पर दवाएं उपलब्ध।
- **प्रधानमंत्री मातृ वन्दना योजना** के तहत 24 लाख 63 हजार 661 लाभार्थियों को रु. 890.84 करोड़ रु. की धनराशि वितरित।
- गरीबों के निःशुल्क इलाज हेतु **'मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा कोष'** का गठन।
- 44 जनपदों में निःशुल्क डायलिसिस की सुविधा उपलब्ध। 68 जनपद चिकित्सालयों में निःशुल्क सी.टी. स्कैन की सुविधा उपलब्ध।

- सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में रोगियों को चिकित्सा सेवाएं उनके द्वार पर उपलब्ध कराये जाने के उद्देश्य से 170 एम.एम.यू. सेवा संचालित। 16.19 लाख रोगी लाभान्वित।
- **एस.जी.पी.जी.आई. लखनऊ में स्टेम सेल रिसर्च सेन्टर, बोन मैरो ट्रांसप्लांट सेन्टर, लीवर ट्रांसप्लांट सेन्टर एवं 60 बेड का ट्रामा सेन्टर क्रियाशील। रोबोटिक सर्जरी की शुरूआत, इमरजेन्सी मेडिसिन एवं रीनल ट्रांसप्लांट सेन्टर निर्माणाधीन।**
- आर.एम.एल. आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ में एम.बी.बी.एस. पाठ्यक्रम प्रारम्भ। प्रदेश के पहले मैटरनल आई.सी.यू. की स्थापना।
- राजकीय मेडिकल कालेज, झांसी, गोरखपुर, मेरठ एवं प्रयागराज में **सुपर स्पेशियलिटी ब्लॉक** निर्मित एवं कानपुर एवं आगरा में सुपर स्पेशियलिटी ब्लॉक निर्माणाधीन।
- के.जी.एम.यू. में प्रदेश का प्रथम इण्टीग्रेटेड स्पाइन सेन्टर एवं स्पोर्ट्स मेडिसिन विभाग स्वीकृत।

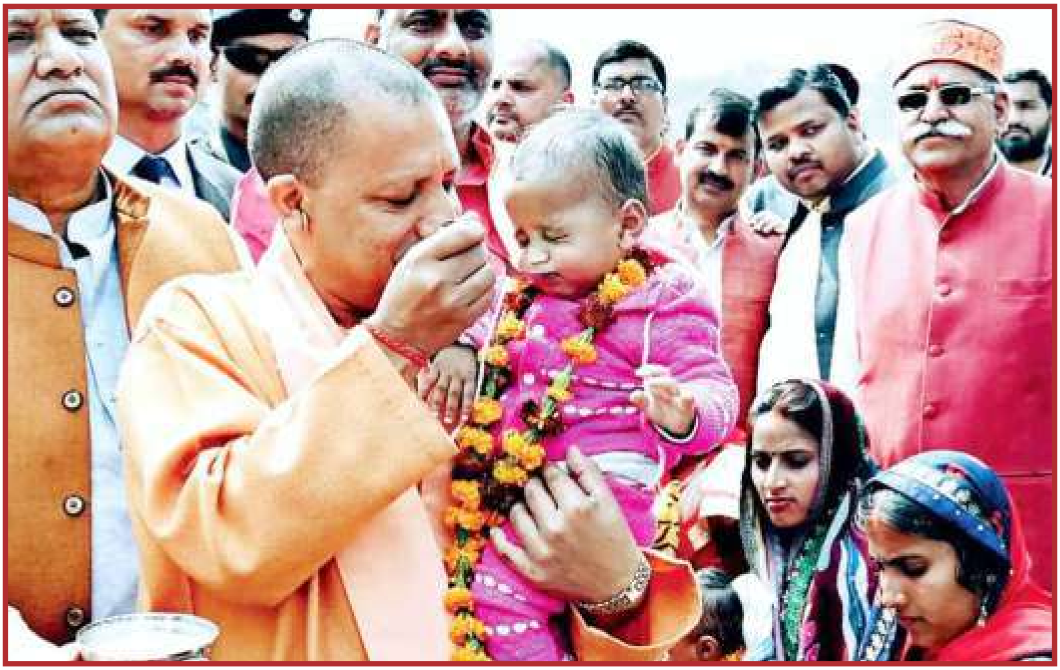

मजबूत बुनियाद का मार्ग प्रशस्त

डिफेन्स एक्सपो – 2020

- डिफेन्स एक्सपो–2020 लखनऊ में सफलतापूर्वक सम्पन्न।
- कार्यक्रम के दौरान 71 एम.ओ.यू., 13 प्रोडक्ट की लॉन्चिंग, 18 तकनीक अन्तरण समझौते, 06 महत्वपूर्ण घोषणा।
- यूपीडा द्वारा उत्तर प्रदेश के डिफेंस इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर में निवेश के लिए विभिन्न उद्यमों के साथ 23 एम.ओ.यू. हस्ताक्षरित। इससे 50 हजार करोड़ का निवेश होगा एवं 5 लाख रोजगार सृजित होंगे।
- उ.प्र. डिफेंस इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर को तकनीकी सहयोग के लिए यूपीडा और डी.आर.डी.ओ. के मध्य एम.ओ.यू. हस्ताक्षरित।
- डिफेंस एक्स्पो–2020 के दौरान रक्षा क्षेत्र में 190 से ज्यादा समझौते हुए।

पूर्वांचल एक्सप्रेस–वे परियोजना

- प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र के विकास के लिए लगभग 341 किमी० लम्बे और 6 लेन चौड़े **पूर्वांचल एक्सप्रेस–वे** का निर्माण गतिमान। दीपावली 2020 तक लोकार्पण।
- एक्सप्रेस–वे पर प्रवेश/निकासी हेतु 11 इंटरचेंज का प्रावधान।
- लड़ाकू विमानों की लैण्डिंग/टेकऑफ जनपद सुल्तानपुर में 3.2 कि.मी. लम्बाई की हवाई पट्टी का निर्माण प्रावधानित।

गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस–वे

- पूर्वांचल एक्सप्रेस–वे को गोरखपुर से जोड़ने के लिए लगभग 92 किमी० लम्बे **गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस–वे का निर्माण प्रगति पर।**

बुंदेलखण्ड एक्सप्रेस–वे परियोजना

- बुंदेलखण्ड क्षेत्र के विकास के लिए रु. 14 हजार 849 करोड़ से लगभग 297 किमी० लम्बे बुंदेलखण्ड एक्सप्रेस–वे का निर्माण कराया जा रहा है। इससे बुंदेलखण्ड क्षेत्र को आगरा–लखनऊ एक्सप्रेस–वे के माध्यम से दिल्ली से जोड़ेगा।

गंगा एक्सप्रेस–वे परियोजना

- जनपद मेरठ से प्रयागराज तक गंगा एक्सप्रेस–वे बनाने का निर्णय।

लोक निर्माण विभाग : नई सड़कें

- अब तक 19360 करोड़ रु. की धनराशि से 11,318 कि.मी. लम्बाई में मार्गों का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण।
- 4,470 करोड़ रु. व्यय कर 9,520 कि.मी. लम्बाई में ग्रामीण मार्गों का निर्माण पूर्ण करते हुए 3254 ग्रामों/बसावटों को सम्पर्क मार्ग से जोड़ा।
- कुम्भ–2019 के दौरान प्रयागराज में 1578.88 करोड़ रु. की लागत से लगभग 646 कि.मी. सड़क का निर्माण।
- तहसील मुख्यालयों व विकास खण्डों को 2 लेन मार्ग से जोड़ने का कार्य गतिमान।
- मेधावी छात्रों के निवास स्थलों तक 113 सड़कों का निर्माण/मरम्मत कर **''डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम गौरव पथ''** के रूप में विकसित।
- **अंतर्राष्ट्रीय/अंतर्राज्यीय मार्गों का विकास।**
- 54 महत्वपूर्ण मार्गों का 1333 करोड़ रुपए की लागत से 667 कि0मी0 लम्बाई का निर्माण कराया जा रहा है।
- तीन वर्षों में 1,81,501 कि.मी. सड़कों को गड्ढामुक्त किया गया।

सेतुओं का निर्माण

- 3430 करोड़ रु. की लागत से 84 दीर्घ सेतु, 32 रेल उपरिगामी सेतु एवं 224 लघु सेतुओं का निर्माण।
- 27 रेल उपरिगामी सेतुओं का अप्रोच मार्ग पूर्ण। 86 रेल उपरिगामी सेतुओं का निर्माण कार्य प्रगति पर।
- 388 लघु सेतुओं का निर्माण कार्य प्रगति पर, जिसमें से 152 लघु सेतुओं का अप्रोच मार्ग पूर्ण।

एयर कनेक्टिविटी

- 07 एयरपोर्ट क्रियाशील हैं, जिनमें 61 गंतव्य स्थानों (लखनऊ से 21, वाराणसी से 19, गोरखपुर से 06, आगरा से 05, प्रयागराज से 06, कानपुर नगर से 03, हिण्डन से 01) के लिए हवाई सेवाएं उपलब्ध।
- 1334 हे. में नोएडा इन्टरनेशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट की स्थापना के लिए भूमि अधिग्रहण।
- बरेली एयरपोर्ट उड़ानों के लिए तैयार। 12 एयरपोर्ट्स का विकास कार्य गतिमान।
- आजमगढ़, अलीगढ़, मुरादाबाद, श्रावस्ती, चित्रकूट, म्योरपुर (सोनभद्र), झांसी में 07 एयरपोर्ट्स विकसित किए जा रहे हैं।
- अयोध्या में अन्तर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट निर्माण के लिए 500 करोड़ रु. का प्रावधान।
- गाजीपुर, सहारनपुर (सरसावां), मेरठ तथा कुशीनगर एवं अयोध्या में भी एयरपोर्ट प्रस्तावित।

मेट्रो सेवाएं

- **लखनऊ मेट्रो रेल परियोजना** के तहत 23 कि.मी. कॉरीडोर (अमौसी से मुन्शी पुलिया) संचालन। अगले चरण में चारबाग से बंसतकुंज तक कुल 11.165 कि.मी. मेट्रो मार्ग निर्माण के लिए कार्यवाही गतिमान।
- **कानपुर मेट्रो रेल परियोजना** के तहत 11076 करोड़ की लागत से 5 वर्षों में 32.4 कि.मी. लम्बे कॉरिडोर का निर्माण कार्य प्रारम्भ।

परिवहन सुविधाएं

- **निर्भया फण्ड योजनाः** महिला यात्रियों की सुरक्षा के दृष्टिगत सभी बसों में पैनिक बटन एवं सी.सी.टी.वी. कैमरों की व्यवस्था करने वाला **उत्तर प्रदेश पहला राज्य**।
- 19 हजार 494 असेवित गांव परिवहन सुविधा से जुड़े। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए **'संकल्प बस सेवा'** का संचालन किया गया।
- नेपाल हेतु अयोध्या से जनकपुर, **लखनऊ–रूपईडीहा– नेपालगंज, दिल्ली से महेन्द्र नगर, पोखरा व नेपालगंज** के लिए अन्तर्राज्यीय बस सेवा।
- ई–पेमेंट से जुर्माना भुगतान की सुविधा हेतु ई–चालान व्यवस्था लागू कर उत्तर प्रदेश देश का **पहला राज्य** बना।
- **रक्षाबंधन पर्व – वर्ष 2019 में 12.03 लाख महिला यात्रियों को निःशुल्क यात्रा प्रदान की गयी।**

शहरों की तरह जगमग गाँव

- सभी आबाद 1 लाख 4 हजार 636 राजस्व गांव एवं 2 लाख 60 हजार 110 मजरे विद्युतीकृत।
- **2 करोड़ 89 लाख 03 हजार उपभोक्ताओं को नियमित विद्युत कनेक्शन।**
- **जनपद मुख्यालयों में 24 घंटे, तहसील मुख्यालयों में 20 घंटे और ग्रामीण क्षेत्रों में 18 घंटे बिजली आपूर्ति।**
- **सौभाग्य योजना** के तहत **1 करोड़ 24 लाख** से अधिक घरों को निःशुल्क विद्युत कनेक्शन देकर **उत्तर प्रदेश देश में प्रथम**।
- **उजाला योजना** के अन्तर्गत **2 करोड़ 60 लाख 80 हजार 6 सौ 68** (बिजली की बचत करने वाले) एल.ई.डी. बल्बों का वितरण। इससे सालाना विद्युत मांग में 700 मेगावाट की कमी तथा 3385 मिलियन यूनिट बिजली एवं रु. 1355 करोड़ की बचत।
- उत्पादन क्षमता **6 हजार 134 मेगावाट** से बढ़ाकर **12 हजार 734 मेगावाट** क्षमता किए जाने हेतु 660 मेगावाट की 10 इकाईयों का निर्माण कार्य प्रगति पर।
- बुन्देलखण्ड क्षेत्र में 4 हजार मेगावाट क्षमता की सौर परियोजनाएं स्थापित करने की कार्यवाही गतिमान।
- बुन्देलखण्ड के किसानों को बिजली बिल के फिक्स चार्ज में 50 प्रतिशत से 75 प्रतिशत की छूट।
- ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में ट्रांसफॉर्मर खराब होने पर क्रमशः 48 घंटे एवं 24 के अंदर मरम्मत/नये ट्रांसफॉर्मर की स्थापना की जा रही है।
- **587 नये 33/11 केवी विद्युत उपकेन्द्र की स्थापना एवं 1 हजार 91 उपकेन्द्रों की क्षमता में वृद्धि।**
- 7786.52 सर्किट किलोमीटर 33 के.वी. लाइनों का निर्माण।
- 24 जनपदों में 30 स्थानों भूमिगत केबिल के कार्य के सापेक्ष 19 जनपदों में 22 परियोनाएं पूर्ण।

- आई.पी.डी.एस. योजना के अन्तर्गत 4024 सर्किट किमी. के सापेक्ष 3682 सर्किट किमी. भूमिगत केबिल का कार्य पूर्ण।
- घर बैठे ऑनलाइन विद्युत संयोजन के लिए **ई–संयोजन ऐप योजना** ।
- 21 लाख 25 हजार 543 उपभोक्ताओं के घरेलू विद्युत बिलों पर सम्पूर्ण सरचार्ज माफ।
- किसानों के 39767 निजी नलकूपों के बिजली बिल पर सम्पूर्ण सरचार्ज माफ।
- 40 लाख स्मार्ट मीटर लगाए जाने की कार्यवाही गतिमान।

अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत

- **"नई सौर ऊर्जा नीति"** लागू करते हुए सौर ऊर्जा सेक्टर में 1535 मेगावाट के 7500 करोड़ रु. के प्रस्ताव स्वीकृत।
- **सौर ऊर्जा इकाई स्थापना पर स्टाम्प शुल्क में शत–प्रतिशत छूट।**
- वर्ष 2014 में 12 मेगावाट सौर उत्पादन की तुलना में वर्ष 2020 में उत्पादन क्षमता बढ़कर 949 मेगावाट हुई।
- अब तक 225 मेगावाट क्षमता के सोलर रूफटॉप स्थापित।
- **पं. दीनदयाल उपाध्याय सोलर स्ट्रीट लाइट योजना** के अन्तर्गत ग्रामीण बाजारों में 25304 सोलर स्ट्रीट लाइट की स्थापना।
- **मुख्यमंत्री समग्र ग्राम्य विकास योजना** में चयनित राजस्व ग्रामों में **13791 सोलर स्ट्रीट लाइट संयंत्रों** की स्थापना।
- **18823 सोलर पम्प** सिंचाई की स्थापना।
- जैव ऊर्जा उद्यम प्रोत्साहन नीति के अन्तर्गत 2480 करोड़ रु. का निजी निवेश आमन्त्रित।
- **वाणिज्यिक भवनों में ऊर्जा बचत हेतु 'ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता 2018' लागू।**

बुलंदियों पर पूंजी निवेश

- **नई औद्योगिक नीति लागू। निवेश फ्रेण्डली 21 नई नीतियां बनाईं।**
- लखनऊ में फरवरी, 2018 में आयोजित उत्तर प्रदेश **इन्वेस्टर्स समिट** में **4.68 लाख करोड़** रुपये के निवेश सम्बन्धी एम.ओ.यू. हस्ताक्षरित।
- **प्रथम ग्राउण्ड ब्रेकिंग सेरेमनी** एवं **द्वितीय ग्राउण्ड ब्रेकिंग सेरेमनी** आयोजनों के माध्यम से लगभग **2 लाख करोड़ रुपये** के निवेश की 371 परियोजनाएं क्रियान्वित। लगभग **5 लाख लोगों को रोजगार।**
- बुन्देलखण्ड में डिफेन्स इण्डस्ट्रियल मैन्यूफैक्चरिंग कॉरीडोर का शिलान्यास। **50 हजार करोड़ रु. के निवेश** से बनने वाले इस कॉरिडोर के जरिए **5 लाख लोगों का रोजगार सृजन होगा।**
- अब **ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट** की तैयारी।
- **निवेश मित्र पोर्टल** के माध्यम से उद्यमियों को 97849 एन.ओ.सी. निर्गत।
- **ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत बिजनेस रिफार्म एक्शन प्लॉन लागू। इससे प्रदेश 92.89 प्रतिशत स्कोर के साथ अग्रणी राज्यों में शामिल।**

ओ.डी.ओ.पी.

- **ओ.डी.ओ.पी. (एक जनपद–एक उत्पाद) सेक्टर में रु. 8,875 करोड़ से अधिक के ऋण वितरित। 6000 कारीगरों/हस्तशिल्पियों को प्रशिक्षण एवं निःशुल्क टूल किट वितरित। 20 हजार कारीगरों/हस्तशिल्पियों को प्रशिक्षण एवं टूल किट वितरण की कार्यवाही गतिमान। अभी तक 5 लाख से अधिक लोगों को रोजगार।**
- ओ.डी.ओ.पी के 11296 उत्पाद अमेजन की वेबसाइट पर उपलब्ध।

विश्वकर्मा श्रम सम्मान

- **7500 कारीगरों/हस्तशिल्पियों को प्रशिक्षणोपरान्त निःशुल्क टूल किट वितरित।**
- **20 हजार कारीगरों/हस्तशिल्पियों को प्रशिक्षण एवं टूल किट वितरण की कार्यवाही गतिमान।**

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम

- प्रदेश में लगभग 90 लाख सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम इकाईयां हैं। इस प्रकार संख्या की दृष्टि से **उत्तर प्रदेश देश में प्रथम।**
- एम.एस.एम.ई. सेक्टर में 5 लाख से अधिक उद्यमियों/हस्तशिल्पियों/ कारीगरों को रु. 33 हजार करोड़ से अधिक का ऋण वितरित।
- प्रदेश से **1 लाख 14 हजार करोड़ रु.** से अधिक का निर्यात। विगत वर्षों से **25 हजार करोड़ रु. अधिक।**

प्रवासी भारतीय दिवस

- प्रदेश में पहली बार 21 से 23 जनवरी, 2019 को वाराणसी में 15वें **प्रवासी भारतीय दिवस** का आयोजन।

- देश का सबसे बड़ा डिफेन्स एक्सपो–2020 लखनऊ में सफलतापूर्वक सम्पन्न।
- 71 एम.ओ.यू., 13 प्रोडक्ट्स की लॉन्चिंग, 18 तकनीक अन्तरण समझौते, 06 महत्वपूर्ण घोषणाओं सहित 100 से अधिक करार हुए।
- यूपीडा द्वारा उत्तर प्रदेश के डिफेंस इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर में निवेश के लिए विभिन्न उद्यमों के साथ 23 एम.ओ.यू. हस्ताक्षरित। इससे 50 हजार करोड़ रु. का निवेश होगा एवं 5 लाख से अधिक रोजगार के अवसर सृजित होंगे।
- डिफेंस एक्स्पो–2020 के दौरान 200 से ज्यादा एम.ओ.यू. हुए।

वन से जुड़े जन

- तीन वर्षों में 39.42 करोड़ पौध रोपण।
- एक ही स्थल प्रयागराज में 08 घंटे में अधिकतम पौध वितरित कर **गिनीज बुक आफ वर्ल्ड रिकार्ड** में नाम दर्ज।
- **गंगा हरीतिमा अभियान** के अन्तर्गत बिजनौर से बलिया तक गंगा के दोनों किनारों पर 09 करोड़ पौधों का रोपण किया गया।
- पॉलीथिन के निर्माण एवं उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया।

हर वर्ग का कल्याण

- **"मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना"** के अन्तर्गत **एक लाख** से अधिक गरीब कन्याओं का विवाह कराया गया। इस योजना के तहत अनुदान राशि 35 हजार रु. से **बढ़ाकर 51000 रु.** किये गये।
- योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन हेतु चन्दौली, बहराइच, सोनभद्र, बलरामपुर, फतेहपुर एवं चित्रकूट को नीति आयोग की रैंकिंग के साथ **नगद पुरस्कार**।
- **वनटांगिया/मुसहर/कोल एवं थारू जनजाति के 38 ग्राम** राजस्व ग्राम घोषित कर विकास की मुख्य धारा में शामिल।
- **27,764 मुसहर, 4,466 वनटांगिया तथा 81 थारू जनजाति के लोगों तथा शेष अन्य पात्र व्यक्तियों को आवास आवंटित।**

वृद्धावस्था पेंशन

- वृद्धावस्था पेंशन प्रतिमाह **400 रु. से बढ़ाकर 500 रु.।** 46 लाख 96 हजार वृद्धजन को पेंशन।

निराश्रित महिला पेंशन

- निराश्रित महिला पेंशन हेतु आयु सीमा की बाध्यता समाप्त करते हुए 23 लाख 49 हजार 898 निराश्रित को पेंशन।

दिव्यांगजन सशक्तीकरण

- दिव्यांगजन पेंशन प्रतिमाह 300 रु. से बढ़ाकर **500 रु.** की गई। 10 लाख 55 हजार 513 दिव्यांगजन को पेंशन।
- बजट प्राविधान 660 करोड़ रु. से बढ़ाकर इस वर्ष 1070 करोड़ रु. किया गया।

राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना

- 331.50 करोड़ रु. की 1,14,896 परिवारों को आर्थिक सहायता।

मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना

- अप्रैल, 2019 से संचालित इस योजना में अब तक 02 लाख 60 हजार से अधिक बालिकाएं लाभान्वित।

श्रम विभाग द्वारा आयोजित विवाह योजना

- पंजीकृत निर्माण श्रमिक (महिला एवं पुरुष) की अधिकतम दो पुत्रियों हेतु अनुमन्य। अब तक कुल 17,121 पात्र लाभान्वित।

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना

- योजना के अन्तर्गत शिशु, किशोर एवं

तरुण श्रेणी में क्रमशः 50 हजार, 5 लाख तथा 10 लाख रु. तक के ऋण का प्रावधान। 34 लाख 53 हजार 760 पात्र लाभान्वित।

प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना

- 18 से 50 वर्ष आयु के खाताधारकों को 330 रुपये वार्षिक प्रीमियम पर 02 लाख रुपये का जीवन बीमा कवर। 58,87,127 लाभान्वित।

जनधन योजना

- सभी परिवारों को **'रुपे'** डेबिट कार्ड सहित कम से कम एक मूल बैंकिंग खाता उपलब्ध कराना। इसमें एक लाख रुपये का दुर्घटना बीमा शामिल है। अब तक 6 करोड़ 05 लाख 85 हजार लोग लाभान्वित। **योजना के क्रियान्वयन में देश में प्रथम** स्थान।

अटल पेंशन योजना

- 30 लाख 55 हजार 615 पात्र लोगों को पेंशन दी जा रही है।
- अनुसूचित जाति और जनजाति के कुल 33 लाख 43 हजार, पिछड़ी जाति के कुल 55 लाख 83 हजार एवं सामान्य वर्ग के 19 लाख से अधिक छात्र–छात्राओं को पूर्वदशम एवं दशमोत्तर छात्रवृत्ति दी गई।
- **सभी 18 मंडलों में अटल आवासीय विद्यालय निर्माण** कार्य गतिमान।
- अल्पसंख्यक व पिछड़े वर्ग के छात्र–छात्राओं को छात्रवृत्ति हेतु अभिभावकों की अधिकतम वार्षिक आय सीमा 2 लाख रु. से बढ़ाकर 2.5 लाख रु. की गयी।
- **94 पंडित दीनदयाल उपाध्याय राजकीय आश्रम** विद्यालय संचालित।
- **प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम** के तहत 42 राजकीय इण्टर कालेज निर्मित।
- अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के तहत दर्ज मामलों के त्वरित निस्तारण के लिए **25 नए कोर्ट गठित**।
- **अल्पसंख्यक महिलाओं को बिना महरम हज पर जाने की सुविधा।**
- अल्पसंख्यक वर्ग के निर्धन व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी के अनुदान हेतु रु. 20,000 की सहायता।

श्रमिक कल्याण

- **प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना** में 5 लाख 23 हजार 246 लाभार्थी पंजीकृत।
- **बढ़ई, दर्जी, टोकरी बुनकर, नाई, सुनार, लोहार, कुम्हार, हलवाई** आदि के प्रोत्साहन हेतु **'विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना'** का शुभारम्भ एवं **'उ0प्र0 माटी कला बोर्ड'** का गठन किया गया।
- 60 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके **श्रमिकों को प्रतिमाह 1000 रु. की पेंशन।** 49,41,825 श्रमिकों का पंजीकरण।
- कार्यस्थल पर श्रमिक की मृत्यु की दशा में 05 लाख रु., स्थायी विकलांगता पर 03 लाख रुपये एवं आंशिक विकलांगता पर 02 लाख रुपये की सहायता का प्रावधान किया गया है।
- बाल श्रम उन्मूलन हेतु **नया सवेरा योजना** के तहत 18,376 बाल श्रमिकों को शिक्षा से जोड़ा गया।

स्वच्छता से संवरे शहर

- प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश देश में **प्रथम स्थान** पर है। **अब तक 15 लाख 63 हजार 105 आवास स्वीकृत।**
- **सभी 75 जनपद खुले में शौच मुक्त (ODF) घोषित।**
- 8 लाख 87 हजार 906 व्यक्तिगत घरेलू शौचालय निर्मित। 652 नगर निकाय खुले में शौच मुक्त (ओ.डी.एफ.) घोषित।
- नगरों में 62 हजार 818 सामुदायिक शौचालयों का निर्माण। इसके अतिरिक्त 652 पिंक शौचालयों (केवल महिलाओं के लिए) का निर्माण।

स्मार्ट सिटी योजना

- लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, आगरा, सहारनपुर, बरेली, झांसी, मुरादाबाद, अलीगढ़ में **रु. 20 हजार करोड़ की परियोजनाओं** का क्रियान्वयन।

अमृत योजना (AMRUT)

- प्रदेश के 60 शहर आच्छादित।

नमामि गंगे

- 15 परियोजनाएं पूर्ण, 19 परियोजनाएं निर्माणाधीन तथा 11 परियोजनाएं निविदा की प्रक्रिया में।
- **कानपुर के सीसामऊ नाले में 140 एम.एल.डी. सीवेज को टैप कर 80 एम.एल.डी. बिनगवां एस.टी.पी. में तथा 60 एम.एल.डी. जाजमऊ एस.टी.पी. में शोधित किया जा रहा है।**
- 140 एम.एल.डी. दीनापुर, वाराणसी में एस.टी.पी. संचालित। इसके बायो गैस से विद्युत उत्पादन भी किया जा रहा है।
- बिजनौर से बलिया तक 155 नालों का शोधन कार्य।

गोवंश का बढ़ा मान

- सभी जनपदों में **2–2 वृहद गोवंश संरक्षण केन्द्र** की स्थापना। **180 करोड़ रु.** स्वीकृत।
- बेसहारा/निराश्रित गोवंशीय पशुओं के भरण–पोषण हेतु **कार्पस फण्ड** सृजित।
- 4,271 अस्थायी गो आश्रय स्थल, 146 कान्हा गोशाला, 385 कांजी हाउस व 109 वृहद गोवंश संरक्षण केन्द्रों में कुल 4,63,566 गोवंश संरक्षित एवं भरण–पोषण हेतु रु. 273.61 करोड़ की व्यवस्था।
- मुख्यमंत्री निराश्रित गोवंश सहभागिता कार्यक्रम में 24,838 गोपालकों को 50,346 गोवंश सुपुर्द।
- 39 गौशालाओं को मण्डी परिषद द्वारा **22.62 करोड़ रु.** की धनराशि जारी।
- बुन्देलखण्ड के 7 जनपदों में **35 पशु आश्रय गृहों** के निर्माण हेतु **10 करोड़ रू.** स्वीकृत।
- 16 नगर निगमों में गोशालाओं को **रु. 17.52 करोड़** निर्गत।
- अब तक 1266.21 लाख पशुओं का टीकाकरण।

दुग्ध उत्पादन व अन्य

- दुग्ध उत्पादन में **उत्तर प्रदेश देश में प्रथम।**
- 305.19 लाख मीट्रिक टन दुग्ध उत्पादन।
- **दुग्ध उत्पादन में प्रतिदिन 50 लाख लीटर की वृद्धि।**
- **09 ग्रीन फील्ड डेयरियों से 1950 हजार लीटर प्रतिदिन दुग्ध उत्पादन।**
- कुक्कुट इकाइयों से 104.13 लाख अण्डों का प्रतिदिन उत्पादन।

मत्स्य पालन

- मत्स्य जलाशयों हेतु न्यूनतम ठेका अवधि 3 वर्ष से बढ़ाकर 10 वर्ष की गई।
- मत्स्य पालकों को 288 करोड़ टन गुणवत्तायुक्त मत्स्य बीजों का वितरण।
- **कम जल तथा कम भूमि में अधिक मत्स्य उत्पाद की नई तकनीक के अन्तर्गत 25 री–सरकुलेट्री एक्वाकल्चर सिस्टम स्थापित।**
- मत्स्य पालकों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा अनुमन्य।
- **नीली क्रान्ति हेतु ब्लू रिवोल्यूशन इन्टीग्रेटेड डेवलपमेन्ट एण्ड मैनेजमेन्ट फॉर फिशरीज** कार्यक्रम।
- निःशुल्क मछुआ दुर्घटना बीमा योजना लागू।
- 448 मछुआ आवासों के सापेक्ष 353 मछुआ आवास निर्माणाधीन तथा 95 आवास के निर्माण हेतु प्रथम किश्त निर्गत।
- 13,4014 मछुआरों को **प्रधानमंत्री सुरक्षा दुर्घटना बीमा योजना** के दायरे में लाया गया।
- 688 मत्स्य नर्सरियों का निर्माण कराया गया।

पर्यटन-संस्कृति में ऊँचे आयाम

- अयोध्या में दीपोत्सव, मथुरा में कृष्णोत्सव, वाराणसी में देव दीपावली तथा बरसाना में रंगोत्सव का आयोजन।
- रु. 133 करोड़ से अयोध्या का समेकित पर्यटन विकास।
- वाराणसी में सांस्कृतिक केन्द्र तथा पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म स्थल बटेश्वर का विकास।
- गोरखपुर के रामगढ़ताल में वाटर स्पोर्ट्स, पीलीभीत टाइगर रिजर्व तथा चन्दौली में देवदरी राजदरी वाटरफॉल का विकास।
- विगत तीन वर्षों में पर्यटकों का रिकार्ड आगमन।
- अयोध्या में दीपोत्सव का भव्य आयोजन, लगातार दो वर्ष **गिनीज बुक आफ वर्ल्ड रिकार्ड** बनाया गया।
- चित्रकूट में कामदगिरि पर्वत पर श्रद्धालुओं/पर्यटकों की सुविधा के लिए रोप–वे का लोकार्पण।
- **काशी विश्वनाथ कॉरिडोर** के विकास के लिए रु. 200 करोड़ का प्रावधान।
- रामायण सर्किट के अन्तर्गत रु. 69.45 करोड़ से चित्रकूट एवं श्रृंगवेरपुर का पर्यटन विकास।
- बुद्धिस्ट सर्किट में रु. 99.97 करोड़ की लागत से श्रावस्ती, कपिलवस्तु एवं कुशीनगर का पर्यटन विकास।
- वाराणसी में क्रूज संचालन हेतु 10.71 करोड़ रु. की व्यवस्था।
- रु. 44.60 करोड़ से **वाराणसी में पर्यटन** विकास।
- रु. 39.73 करोड़ से गोवर्धन (मथुरा) का पर्यटन विकास।
- स्पिरीचुअल सर्किट के अन्तर्गत गोरखपुर, देवीपाटन, डुमरियागंज के लिए रु0 21.16 करोड़ तथा जेवर, दादरी, नोएडा, खुर्जा एवं बांदा के पर्यटन विकास के लिए रु0 14.52 करोड़ का कार्य स्वीकृत।
- आगरा में शाहजहाँ पार्क एवं मेहताब बाग–कछपुरा का कार्य एवं वृन्दावन में बाँके बिहारी जी मन्दिर क्षेत्र में पर्यटन विकास।
- **दुधवा टाईगर रिजर्व तथा पीलीभीत टाईगर रिजर्व स्थलों का विकास।**
- अयोध्या में रामलीला का मंचन पुनः प्रारम्भ।
- थारू जनजाति पर आधारित विशेष संग्रहालय की स्थापना की कार्यवाही।
- **मगहर में संत कबीर अकादमी की स्थापना।**
- राजभवन में स्वामी विवेकानन्द की मूर्ति एवं लोक भवन में भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा स्थापित।
- **गोरखपुर में 5000 की दर्शक क्षमता के प्रेक्षागृह एवं खुले मंच की स्थापना।**

रामायण क्षेत्र के विशेषज्ञों का सम्मान

- रामायण संस्कृति को प्रचार हेतु योगदान देने वाले कलाकारों का सम्मान।
- गज़ल, दादरा, ख्याल एवं ठुमरी क्षेत्र के 04 कलाकारों को बेगम अख्तर पुरस्कार।
- 60 वर्ष से अधिक आयु के 321 **वृद्ध एवं विपन्न कलाकारों को रु. 2000 प्रतिमाह पेंशन।**

मातृशक्ति का सम्मान

- प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में गरीब महिलाओं को 1 करोड़ 47 लाख निःशुल्क गैस कनेक्शन वितरित। देश में पहला स्थान।
- कन्या भ्रूण हत्या रोकने तथा बालिकाओं के प्रति सकारात्मक सोच विकसित करने के लिए **मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना** प्रारम्भ।
- मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजनान्तर्गत 1 लाख से अधिक निर्धन कन्याओं का विवाह। सहायता धनराशि **रु. 35 हजार से बढ़ाकर रु. 51,000 की गयी।**
- प्रधानमंत्री मातृ वन्दना योजना से 23 लाख 76 हजार माताएं लाभान्वित।
- विधवा पेंशन के अन्तर्गत 21 लाख 69 हजार 898 महिलाओं को पेंशन।
- महिला हेल्पलाइन 1090 सेवा में 98.80 प्रतिशत शिकायतों का निस्तारण।
- हर जिले में एंटी रोमियो स्क्वॉयड का गठन।
- हिंसा से पीड़ित महिलाओं के लिए वन स्टाप सेन्टर की स्थापना।
- **निराश्रित महिला पेंशन हेतु आयु सीमा की बाध्यता समाप्त।**
- वर्ष 2019–20 में 24 लाख 75 हजार 224 निराश्रित महिलाओं को 500 रु. प्रतिमाह की दर से पेंशन दी गई।
- 41 जनपदों के 91 हजार 179 आंगनबाड़ी केन्दों पर गोदभराई एवं अन्नप्राशन का आयोजन। अब तक कुल 9 लाख 70 हजार 65 कार्यक्रमों का आयोजन।
- 'शबरी संकल्प अभियान' 39 जनपदों में संचालित।
- पोषण एवं स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारी देने के लिए **पोषण पखवाड़ों** का आयोजन।

खेलोगे तो बढ़ोगे

23वां राष्ट्रीय युवा उत्सव

- स्वामी विवेकानन्द जयन्ती पर 12 से 16 जनवरी, 2020 तक लखनऊ में राष्ट्रीय युवा उत्सव का आयोजन। 7,000 युवाओं द्वारा प्रतिभाग।

खेलों को बढ़ावा

- 19 जनपदों में 16 खेलों के प्रशिक्षण के लिए 890 खिलाड़ियों के लिए 44 छात्रावास।
- 21वें कामनवेल्थ गेम्स में 18 पदक जीतने के लिए 18 खिलाड़ियों को पुरस्कार स्वरूप 2 करोड़ 60 लाख रु. प्रदत्त।
- **18वें एशियन गेम्स में पद विजेता 46 खिलाड़ियों को 3 करोड़ 90 लाख रु. प्रदत्त।**
- लक्ष्मण/रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार से 44 खिलाड़ी पुरस्कृत।
- रियो ओलम्पिक गेम्स में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली सुश्री पी0वी0 सिंन्धु, सुश्री साक्षी मलिक, सुश्री दीपा करमाकर को 01–01 करोड़ रुपये का पुरस्कार।
- आई.सी.सी. महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप–2017 लन्दन में रजत पदक प्राप्त करने वाली भारतीय टीम की सदस्य सुश्री दीप्ति शर्मा एवं पूनम यादव को रु. 8–8 लाख का नकद पुरस्कार।
- ''खूब खेलो–खूब पढ़ो'' पखवाड़े में कुल 186 प्रतियोगिताओं का आयोजन।
- खेल किट हेतु धनराशि रू. 1000 से बढ़ाकर रू. 2500 की गयी।
- खेलो इण्डिया योजना के अन्तर्गत प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में खेल अवस्थापना सुविधाओं का सृजन।

संस्कृति को नमन

- कुम्भ में 7 हजार से अधिक लोगों ने पेंटिंग वॉल पर हाथों की छाप से हस्तलिपि चित्रकारी का विश्व रिकार्ड बनाया। गिनीज़ बुक ऑफ वर्ल्ड रिकार्ड में दर्ज हुआ।
- प्रयागराज कुम्भ–2019 में 503 शटल बसों का एक साथ एक रूट पर सफल संचालन करने के साथ ही गिनीज़ बुक ऑफ वर्ल्ड रिकार्ड में नाम दर्ज हुआ।
- सेनिटेशन के लिए कुम्भ मेले का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकार्ड में दर्ज किया गया।
- 22 हजार स्वच्छताग्रहियों ने कुम्भ को स्वच्छ बनाने में योगदान दिया।
- आस्था विश्वास और श्रद्धा से सराबोर कुम्भ मेले को यूनेस्को ने **'मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर'** के रूप में मान्यता दी।
- कुम्भ–2019 में पहली बार 72 देशों के राजदूतों एवं संयुक्त राष्ट्र संघ के 193 देशों में से 187 देशों के प्रतिनिधियों ने दिव्य एवं भव्य कुम्भ के वैभव का अवलोकन किया।
- कुम्भ–2019 में 1,22,500 से अधिक इकोफ्रेन्डली शौचालयों का रिकार्ड निर्माण किया गया।
- कुम्भ–2019 में सफाई कार्य में अप्रतिम योगदान के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा सफाईकर्मियों के पांव पखार कर सम्मानित किया गया।
- कैलाश मानसरोवार यात्रियों की अनुदान राशि 50 हजार रु. से बढ़ाकर 1 लाख रु. प्रति यात्री की गयी।
- सिंधु दर्शन का अनुदान 20 हजार रु. प्रति यात्री की गयी।

आई.टी. एवं इलेक्ट्रॉनिक्स

- मुख्यमंत्री हेल्पलाइन सेवा (1076) प्रभावी ढंग से क्रियान्वित।
- प्रदेश में ई–टेण्डरिंग प्रणाली लागू।
- सर्वोत्तम परफार्मेन्स के लिए उत्तर प्रदेश को 'बेस्ट परफारमेन्स अवार्ड'।
- वर्तमान में कुल 1817 स्टार्ट अप इकाईयां एवं 17 इन्क्यूबेटर्स कार्यरत।
- स्टेट स्टार्ट–अप रैंकिंग 2018 में 'एस्पायरिंग लीडर' के रूप में सम्मानित।
- ग्रेटर नोएडा में 100 एकड़ क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर (ई.एम.सी.) का विकास।
- ई.एम.सी. में अगले वर्षों में रु. 3000 करोड़ के निवेश से 30 हजार लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार एवं 1 लाख लोगों को अप्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा।
- ई.एम.सी. में चीन, ताइवान और कोरिया आदि की कम्पनियों द्वारा निवेश।
- मेरठ, आगरा, गोरखपुर, कानपुर, वाराणसी, लखनऊ तथा बरेली में रु. 150 करोड़ के निवेश एवं 15000 रोजगार संभावनाओंयुक्त आई.टी. पार्क की स्थापना।
- 34 विभागों की 254 शासकीय सेवायें ई–डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के माध्यम से उपलब्ध।
- 9 जनपदों में मेगा डिजिधन मेले का आयोजन।
- स्टेट डाटा सेन्टर की स्थापना, जिसमें मुख्यमंत्री कार्यालय सहित 61 सरकारी विभागों की 250 सेवाएं आम जनमानस को उपलब्ध।

मंत्रिपरिषद के महत्वपूर्ण निर्णय

- पहली कैबिनेट बैठक में प्रदेश सरकार ने लघु व सीमान्त किसानों का 01 लाख रुपये तक का फसली ऋण माफ माफ करने का निर्णय लिया।
- अवैध पशु वधशालाओं को बन्द करने एवं यांत्रिक पशु वधशालाओं पर प्रतिबन्ध लगाने सम्बन्धी शासनादेशों को सख्ती से लागू करने का फैसला।
- प्रत्येक जनपद में एण्टी रोमियो स्क्वायड के गठन और संचालन सम्बन्धी प्रस्ताव को मंजूरी।
- ग्रामीण क्षेत्रों में 48 घण्टे में क्षतिग्रस्त विद्युत ट्रांसफॉर्मर को बदलने की नई व्यवस्था।
- प्रदेश में 487 रु0 प्रति कुन्तल की दर से एक लाख मीट्रिक टन आलू की खरीद।
- इंसेफेलाइटिस एवं अन्य जल एवं विषाणु जनित बीमारियों के रोकथाम के लिए प्रभावी उपाय करने का निर्णय।
- गन्ना मूल्य का समय से भुगतान सुनिश्चित कराने एवं बकाया भुगतान न करने वाली चीनी मिलों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई का निर्णय।
- प्रदेश के हर घर को सातों दिन, चौबीसों घण्टे विद्युत आपूर्ति करने के लिए भारत सरकार के साथ साइन करने हेतु निर्धारित सहमति पत्र अनुमोदित।
- बुन्देलखण्ड के ग्रामीण क्षेत्रों में पेय जल समस्या के समाधान की कार्य योजना को मंजूरी।
- 14 अप्रैल, 2017 से ग्रामीण इलाकों को 18 घण्टे, तहसील व बुन्देलखण्ड क्षेत्र को 20 घण्टे एवं सभी जनपद मुख्यालयों को 24 घण्टे की विद्युत आपूर्ति।
- घरेलू, वाणिज्यिक, निजी संस्थान, निजी नलकूप एवं लघु उद्योगों के लिए विलम्बित भुगतान अधिभार ऐमनेस्टी योजना मंजूर।
- गोरखपुर सिविल टर्मिनल का नामकरण महायोगी गोरखनाथ जी के नाम पर तथा आगरा सिविल टर्मिनल का नामकरण पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम पर करने का निर्णय।
- प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना तथा पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना को 2 वर्षों के लिए लागू करने का निर्णय।
- हर जिले में एण्टी भू–माफिया टास्क फोर्स स्थापित करने का निर्णय।
- सार्वजनिक अवकाश निर्बन्धित अवकाशों की श्रेणी में सम्मिलित। महापुरुषों की जयन्ती पर प्रदेश की सभी शिक्षण संस्थाओं में सभा/गोष्ठी/सेमिनार आयोजित करने का फैसला।
- शासकीय विभागों में ई–टेंडरिंग तथा ई–प्रोक्योरमेंट प्रणाली लागू किये जाने का फैसला।
- 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस के रूप में मनाने का निर्णय।
- नगर पालिका परिषद मथुरा एवं नगर पालिका परिषद वृन्दावन को मिलाकर मथुरा–वृन्दावन नगर निगम के गठन का फैसला।
- नगर पालिका परिषद अयोध्या एवं नगर पालिका परिषद फैजाबाद को मिलाकर अयोध्या नगर निगम का दर्जा।
- दिव्यांग भरण पोषण योजना की मासिक अनुदान राशि 300 रु० प्रतिमाह से बढ़ाकर

500 रु० प्रतिमाह करने का फैसला।

- प्रादेशिक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के चिकित्साधिकारियों की अधिवर्षता आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष करने का निर्णय।
- पूर्वान्चल एक्सप्रेस–वे परियोजना के आठों पैकेजों को ई0पी0सी0 पद्धति पर अग्रेत्तर क्रियान्वयन।
- पं. दीनदयाल उपाध्याय जन्मशती वर्ष मनाने के सम्बन्ध में मंत्रिपरिषद समिति की संस्तुतियां अनुमोदित।
- नगर पालिका परिषद मुगलसराय का नाम पं. दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम से 'दीनदयाल नगर' किए जाने का निर्णय।
- उ.प्र. सचिवालय में पत्रावलियों के रख–रखाव के लिए ई–ऑफिस।
- 'समाजवादी किसान एवं सर्वहित बीमा योजना' का नाम परिवर्तित कर 'मुख्यमंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना' किया गया।
- 68 जनपदों में संचालित होगी पं0 दीनदयाल उपाध्याय किसान समृद्धि योजना।
- समूह 'ख' के सभी अराजपत्रित पद, समूह 'ग' एवं समूह 'घ' के पदों के लिए साक्षात्कार समाप्त करने का निर्णय।
- जनपद गाजियाबाद की इन्दिरापुरम योजना के अन्तर्गत जी0डी0ए0 की भूमि पर कैलाश मानसरोवर भवन का निर्माण कराए जाने का निर्णय।
- जनपद अमरोहा एवं हापुड़ के कार्तिक पूर्णिमा मेला गढ़मुक्तेश्वर, रामायण मेला–चित्रकूट, माँ ललिता देवी शक्तिपीठ अमावस्या मेला–नैमिषारण्य, माँ पाटेश्वरी शक्तिपीठ–देवीपाटन तुलसीपुर मेला, तथा माँ विन्ध्यवासिनी शक्तिपीठ मेला, मीरजापुर के प्रान्तीयकरण का निर्णय।
- पं. दीनदयाल उपाध्याय खादी विपणन विकास सहायता के अन्तर्गत दी जाने वाली छूट का एक अंश सीधे कामगारों को दिए जाने का निर्णय।
- मुख्यमंत्री कृषक धन योजना, मुख्यमंत्री सामुदायिक वानिकी योजना तथा मुख्यमंत्री फलोद्यान योजना लागू।
- प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों के छात्र–छात्राओं को निःशुल्क जूता, मोजा एवं स्वेटर।
- मुख्यमंत्री हेल्पलाइन की स्थापना और संचालन के लिए लखनऊ में 500 सीटों के कॉल सेण्टर की स्थापना।
- प्रयागराज मेला प्राधिकरण के गठन का निर्णय।
- रामगढ़ताल, गोरखपुर में प्रेक्षागृह एवं वॉटर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के निर्माण हेतु 05 एकड़ भूमि पर्यटन विभाग को निःशुल्क हस्तांतरित।
- तीन तलाक से पीड़ित मुस्लिम महिलाओं के सम्बन्ध में भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित प्राविधानों को सैद्धान्तिक सहमति।
- 'उ0प्र0 भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन एवं सेवाशर्त विनियमन) नियमावली–2009 में संशोधन।
- उ.प्र. मेट्रो रेल कारपोरेशन का गठन।
- मुख्यमंत्री समग्र ग्राम विकास योजना।
- 'एक जनपद एक उत्पाद योजना' के क्रियान्वयन का निर्णय।
- काशी हिन्दू विश्वविद्यालय परिसर में वैदिक विज्ञान केन्द्र की स्थापना।
- मुख्यमंत्री आवास योजना–ग्रामीण।
- समस्त उचित दर दुकानों में ई–पॉस मशीन स्थापित कर उनके माध्यम से लाभार्थियों को खाद्यान्न वितरण।

- उ.प्र. के मूल निवासी शहीद सैनिकों के आश्रितों को अनुकम्पा नियुक्ति।
- बुन्देलखण्ड क्षेत्र में खरीफ आच्छादन में वृद्धि हेतु विभिन्न फसलों की उन्नतशील प्रमाणित एवं संकर प्रजातियों के बीजों पर राज्य सरकार द्वारा विशेष अनुदान।
- मुख्यमंत्री व्यापारी दुर्घटना बीमा योजना में बीमा राशि 05 लाख रु0 से बढ़ाकर 10 लाख रु0 की गयी।
- आंगनबाड़ी केन्द्र पर 03 से 06 वर्ष के बच्चों को गर्म खाना पकाकर खिलाने का निर्णय।
- प्रधानमंत्री राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा मिशन।
- जनपद मथुरा में बरसाना, गोकुल, गोवर्धन, नन्दगांव, राधाकुण्ड तथा बलदेव मद्य निषेध क्षेत्र घोषित।
- मगहर, जनपद संत कबीर नगर में कबीर दास अकादमी की स्थापना।
- श्री काशी विश्वनाथ विशिष्ट क्षेत्र विकास परिषद अध्यादेश–2018
- पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों हेतु रोजगारपरक प्रशिक्षण योजना।
- लाभार्थीपरक एवं कल्याणकारी योजनाओं का लाभ वंचित पात्र लोगों को उपलब्ध कराने हेतु सर्वेक्षण।
- उ.प्र. माटी कला बोर्ड का गठन।
- लोकतंत्र सेनानियों एवं उनके पात्र आश्रितों की सम्मान राशि 15 हजार रु. से बढ़ाकर 20 हजार रु. प्रतिमाह।
- नगर प्रतिकर भत्ते तथा मकान किराए भत्ते की 01 दिसम्बर, 2008 से लागू दरें 01 जुलाई, 2018 से दोगुना।
- गन्ना किसानों का पेराई सत्र– 2017–18 का बकाया गन्ना मूल्य भुगतान के लिए 500 करोड़ रु0 की वित्तीय सहायता।
- 'द उत्तर रियल स्टेट (रेगुलेशन एण्ड डेवलपमेन्ट) (एग्रीमेन्ट फॉर सेल रूल्स) 2018' अनुमोदित।
- जनपद, मण्डल एवं नगर निगम इलाहाबाद का नाम परिवर्तित कर जनपद 'प्रयागराज'।
- जनपद व मंडल फैजाबाद का नाम परिवर्तित कर अयोध्या किए जाने का निर्णय।
- दीन दयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय परिसर में गुरु श्री गोरक्षनाथ शोध पीठ की स्थापना।
- आंगनबाड़ी कार्यकत्री/मिनी आंगनबाड़ी कार्यकत्री को 500 रु0 प्रतिमाह तथा आंगनबाड़ी सहायिका को 250 रु0 प्रतिमाह परफार्मेन्स लिंक्ड इन्सेन्टिव।
- विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना।
- सीवर/सेप्टिक टैंक की सफाई के दौरान मृत्यु होने पर आश्रित परिवार को 10 लाख रु. की तत्काल राहत।
- डिफेन्स कॉरिडोर के लिए लैण्ड बैंक की व्यवस्था।
- पूर्वांचल विकास बोर्ड का गठन।
- बुन्देलखण्ड विकास बोर्ड का गठन।
- उ.प्र. व्यापारी कल्याण बोर्ड का गठन।
- उ.प्र. सतर्कता अधिष्ठान के 10 सेक्टर्स/इकाइयां थाना घोषित।
- समस्त ग्रामीण व शहरी स्थानीय निकायों में अस्थायी गोवंश आश्रय स्थल की स्थापना व संचालन नीति।
- मत्स्य आखेट पट्टा/ठेका अधिकार नीति।
- सरकारी सेवाओं की सभी श्रेणियों तथा शैक्षिक संस्थाओं में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए अधिकतम 10 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था।
- जनपद चन्दौली की तहसील मुगलसराय

का नाम पं. दीन दयाल उपाध्याय नगर किए जाने का निर्णय।

- कुष्ठ रोग से प्रभावित परिवार को मुख्यमंत्री आवास योजना–ग्रामीण की पात्रता में सम्मिलित।
- 'बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस–वे' परियोजना के निर्माण के लिए 06 पैकेजों का ई.पी.सी. पद्धति पर क्रियान्वयन।
- गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस–वे परियोजना के वित्त पोषण तथा निर्माणकर्ताओं के चयन सम्बन्धी अभिलेख अनुमोदित।
- एस.जी.पी.जी.आई., लखनऊ के संकायी सदस्यों एवं गैर संकायी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को एम्स के अनुरूप भत्ते अनुमन्य।
- 'गंगा एक्सप्रेस–वे' निर्माण को सैद्धान्तिक सहमति।
- भारद्वाज ऋषि के आश्रम, श्रृंग्वेरपुर धाम प्रयागराज–चित्रकूट मार्ग पर पहाड़ी नामक स्थान पर स्थित महर्षि वाल्मीकि के आश्रम का सौन्दर्यीकरण एवं विकास।
- मूल्य समर्थन योजना के अन्तर्गत गेहूं क्रय नीति लागू।
- महिलाओं के विरुद्ध आपराधिक मुकदमों के अतिशीघ्र निस्तारण हेतु वाराणसी में एक फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना।
- मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना लागू।
- लखनऊ, प्रयागराज, आगरा, गाजियाबाद, कानपुर, गोरखपुर, वाराणसी, मथुरा एवं शाहजहांपुर में वातानुकूलित मिडी इलेक्ट्रिक बसों का संचालन।
- अयोध्या में पर्यटन आकर्षण की दृष्टि से भगवान श्रीराम पर आधारित डिजिटल म्यूजियम, इण्टरप्रेटेशन सेण्टर, लाइब्रेरी, पार्किंग, फूड प्लाजा, लैण्डस्केपिंग एवं श्रीराम प्रतिमा एवं अन्य मूलभूत पर्यटक सुविधाओं का सृजन।
- स्कूलों के मध्यान्ह भोजन में कार्यरत रसोइयों व कुक–कम–हेल्पर का मानदेय बढ़ाकर 1500 रु0 प्रतिमाह।
- वृद्धावस्था पेंशन 400 रु. से बढ़ाकर 500 रु. प्रतिमाह।
- 'मा0 मुख्यमंत्री निराश्रित/बेसहारा गोवंश सहभागिता योजना'।
- 'उ0प्र0 इलेक्ट्रिक वाहन मैन्युफैक्चरिंग नीति–2019' का प्रख्यापन।
- धान क्रय नीति अनुमोदित। प्रथम बार बटाईदार व कॉन्ट्रैक्ट फारमर्स से भी धान खरीद।
- 'उत्तर प्रदेश कृषि निर्यात नीति–2019'।
- 07 नगर निगमों – मेरठ, गाजियाबाद, अयोध्या, फिरोजाबाद, गोरखपुर, मथुरा–वृन्दावन एवं शाहजहांपुर को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित किए जाने का निर्णय।
- मक्का क्रय नीति अनुमोदित।
- बेसिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत महानिदेशक, स्कूल शिक्षा का पद सृजित।
- लखनऊ, मेरठ, प्रयागराज, आगरा, गाजियाबाद, कानपुर, वाराणसी, मुरादाबाद, अलीगढ़, झांसी, बरेली एवं गोरखपुर, शाहजहांपुर, मथुरा–वृन्दावन में वातानुकूलित मिडी इलेक्ट्रिक बसों के संचालन।
- अयोध्या के दीपोत्सव मेले का प्रान्तीयकरण।
- उ0प्र0 राज्य सेप्टेज प्रबन्धन नीति।
- प्राविधिक शिक्षा विभाग के शिक्षकों को सातवें वेतन आयोग की संस्तुतियों के आधार पर वेतनमानों का पुनरीक्षण।

- वाराणसी में नवीन थाना लालपुर–पाण्डेयपुर तथा पर्यटक पुलिस थाना की स्थापना।
- 'बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस–वे परियोजना' के विभिन्न पैकेजों हेतु निर्माणकर्ताओं का चयन।
- 'गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस–वे परियोजना' के विभिन्न पैकेजों हेतु निर्माणकर्ताओं का चयन अनुमोदित।
- अलीगढ़ मण्डल में 'राजा महेन्द्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़' की स्थापना।
- उ0प्र0 नगर पालिका (भवन या भूमि या दोनों के वार्षिक मूल्य पर कर) नियमावली–2019 प्रख्यापित।
- उ0प्र0 ई–स्टाम्पिंग नियमावली–2013 संशोधित।
- पावरलूम बुनकरों को विद्युत दर में छूट।
- नोएडा सेक्टर–71 से ग्रेटर नोएडा नॉलेज पार्क–5 तक मेट्रो कॉरिडोर परियोजना अनुमोदित।
- सिद्धार्थनगर की नगर पंचायत शोहरतगढ़, सीतापुर की नगर पंचायत तम्बौर अहमदाबाद, रायबरेली की नगर पंचायत महाराजगंज, जालौन की नगर पालिका परिषद, कोंच, संतकबीरनगर की नगर पालिका परिषद, खलीलाबाद, नगर निगम, लखनऊ एवं नगर निगम, वाराणसी के सीमा विस्तार का निर्णय।
- जनपद महराजगंज के ग्राम बृजमनगंज, बस्ती के कस्बा भानपुर, लखीमपुर खीरी की ग्राम सभा निघासन, संतकबीरनगर के ग्राम पंचायत बेलहर कला एवं बेलहर खुर्द को मिलाकर नगर पंचायत बनाए जाने का निर्णय।
- मैनपुरी के ग्राम सभा बरनाहल, सिद्धार्थनगर के बिस्कोहर बाजार, जौनपुर के ग्राम कचगांव, संतकबीरनगर के ग्राम बाघनगर उर्फ बखिरा, मऊ के ग्राम कुर्थीजाफरपुर, प्रतापगढ़ के अन्तर्गत सुवंशा बाजार, सिद्धार्थनगर के बर्डपुर शहर (ग्राम पंचायत) को नगर पंचायत बनाए जाने का निर्णय।
- उ0प्र0 रक्षा तथा एयरोस्पेस इकाई एवं रोजगार प्रोत्साहन (प्रथम संशोधन) नीति 2019
- जनपद सुल्तानपुर की तहसील सदर के 29 राजस्व ग्राम तहसील बल्दीराय में शामिल।
- पाक्सो एक्ट के मामलों के शीघ्र निस्तारण के लिए 218 नियमित न्यायालयों की स्थापना।
- नगर निगम अयोध्या, नगर निगम, गोरखपुर, नगर निगम, फिरोजाबाद, कुशीनगर की नगर पालिका परिषद, पडरौना का सीमा विस्तार किया गया।
- जनपद शाहजहाँपुर की ग्राम पंचायत, बण्डा, बहराइच के ग्राम पयागपुर को नगर पंचायत, पयागपुर, सिद्धार्थनगर के ग्राम बढ़नी चाफा, बदायूं की ग्राम पंचायत, दहगवां, कानपुर देहात के कस्बा मूसानगर, जालौन की ग्राम पंचायत एट, सिद्धार्थनगर के भारत भारी, गोरखपुर के ग्राम चौमुखा (कैम्पियरगंज), को नगर पंचायत बनाया गया।
- जिला वाराणसी के ग्राम लोहता, कुशीनगर के ग्राम फाजिलनगर, ग्राम दुदही, कौशाम्बी के दारानगर कड़ाधाम, बस्ती के ग्राम गायघाट, सिद्धार्थनगर के कस्बा इटवा, फर्रूखाबाद के ग्राम नवाबगंज, फिरोजाबाद के ग्राम मक्खनपुर को नगर पंचायत बनाया गया।
- आजमगढ़ की नगर पंचायत अजमतगढ़, बाराबंकी की नगर पंचायत बंकी, ललितपुर

की नगर पंचायत महरौनी, बस्ती की नगर पंचायत बभनान बाजार को नगर पंचायत बनाया गया।

- बुन्देलखण्ड क्षेत्र, विन्ध्य क्षेत्र तथा गुणता प्रभावित ग्रामों में पेयजल के लिए परियोजना के क्रियान्वयन सम्बन्धी निर्णय।
- नगर निगम शाहजहांपुर, नगर निगम आगरा, हाथरस की नगर पालिका परिषद हाथरस, महराजगंज की नगर पालिका परिषद महराजगंज, अम्बेडकरनगर की नगर पालिका परिषद जलालपुर, सन्तकबीरनगर की नगर पंचायत मेंहदावल, महराजगंज की नगर पंचायत आनन्दनगर की सीमा विस्तार किया गया।
- सुल्तानपुर के ग्राम लम्भुआ, अलीगढ़ के ग्राम मडराक, कुशीनगर के ग्राम तमकुहीराज, आजमगढ़ की जहानागंज बाजार को नगर पंचायत जहानागंज, जौनपुर के ग्राम गौरा बादशाहपुर, कानपुर देहात के कस्बा राजपुर, महराजगंज के ग्राम पनियरा, महराजगंज के ग्राम परतावल, लखनऊ के मोहनलालगंज तहसील मुख्यालय को नगर पंचायत बनाया गया।
- जनपद प्रयागराज के बहादुरपुर ब्लॉक के अन्तर्गत ग्राम कोटवा में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना।
- संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ में मेडिकल टेक्नोलॉजी के छात्रों हेतु 200 बेड छात्रावास का निर्माण।
- लखनऊ (नगर) एवं गौतमबुद्धनगर में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू।
- 'मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना' का क्रियान्वयन।
- 'मुख्यमंत्री पर्यटन संवर्धन योजना' के क्रियान्वयन हेतु प्रक्रिया निर्धारित।
- जनपद मथुरा में गोवर्धन परिक्रमा/गिरिराज परिक्रमा के चारों ओर सर्विस रोड के निर्माण।
- विकास प्राधिकरणों तथा उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद में ओ.टी.एस. 2020 योजना लागू।
- 16 परिक्षेत्रीय मुख्यालयों पर एक–एक साइबर क्राइम पुलिस थाने की स्थापना।
- आबकारी विभाग की सम्पूर्ण कार्यप्रणाली ऑनलाइन।
- रजिस्ट्रीकरण शुल्क की सारणी में संशोधन।
- उ.प्र. भूगर्भ जल (प्रबन्धन एवं नियमन) नियमावली, 2020
- सोनभद्र में ओबरा नई तहसील बनी।
- उ.प्र. पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम के कार्मियों की सेवानिवृत्ति हेतु अधिवर्षता आयु 58 वर्ष से बढ़ाकर 60 वर्ष की गयी।
- वाणिज्यिक विवादों के निस्तारण हेतु 13 जनपदों में कॉमर्शियल कोर्ट्स का गठन।
- 2011 की सामाजिक एवं आर्थिक जनगणना में छूटे हुए पात्र लाभार्थियों को आयुष्मान भारत–प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का लाभ।
- उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद तथा विकास प्राधिकरणों द्वारा पायलेट प्रोजेक्ट के रूप में 'लैण्ड पूलिंग स्कीम' क्रियान्वयन नीति।
- अयोध्या स्थित हवाई पट्टी को एयरपोर्ट के रूप में विकसित करने का निर्णय।
- उत्तर प्रदेश सूक्ष्म एवं लघु उद्योग तकनीकी (टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन) योजना लागू।
- चीनी मिलों को वित्तीय सहायता देने की कटऑफ डेट बढ़ायी गयी।

3 वर्ष में
मथुरा का विकास

मथुरा एक एतिहासिक नगर है। आज यह धार्मिक पर्यटन स्थल के रूप में प्रसिद्ध है। मथुरा भारतीय संस्कृति एवं सभ्यता का केन्द्र रहा है। भारतीय धर्म, दर्शन, कला एवं साहित्य के निर्माण तथा विकास में मथुरा का पूर्ण योगदान रहा है। भगवान श्री कृष्ण के जन्म एवं उनकी बाल लीलाओं के लिए प्रसिद्ध है। यहां अनकों प्रसिद्ध मन्दिर हैं। श्री कृष्ण जन्म स्थान, श्री बांके बिहारी जी, द्वारिकाधीश, भूतेश्वर महादेव, रंगनाथ, पागल बाबा, राधा रमण के अतिरिक्त गोकुल, महावन, बल्देव, गोवर्धन, बरसाना, नन्दगांव आदि दर्शनीय स्थल है।

जनपद की भौगोलिक क्षेत्रफल 3329.4 वर्ग किमी.। जनपद की प्रमुख नदी यमुना है। 2011 की जनगणना के अनुसार जनपद की कुल आबादी 25 लाख 47 हजार है जिसमें पुरुषों की संख्या–13 लाख 67 हजार एवं महिलाओं की संख्या–11 लाख 80 हजार थी। जनपद में एक लोकसभा तथा पांच विधानसभा क्षेत्र हैं।

अवस्थापना सुविधाएं

- रु. 331.813 करोड से नई सड़कों के अन्तर्गत 129.81 किमी. सड़कों का निर्माण।
- रु. 299.99 करोड़ लागत से अमृत योजना के तहत सीवर एवं गृह संयोजन।
- सड़कों को गढ्ढामुक्त योजनान्तर्गत रु. 228.123 करोड़ से 2173.663 कि.मी. सड़क गढ्ढामुक्त।

- रु. 145 करोड़ की लागत से निर्मित 400 के.वी. उपकेन्द्र नौहझील का निर्माण/ऊर्जीकरण कार्य।
- रु. 136 करोड़ की लागत से गोवर्धन रिंग रोड योजना के अन्तर्गत 11.95 कि.मी. गोवर्धन बाई–पास का निर्माण कार्य।
- रु. 134.949 करोड से ओ.डी.आर.एम.डी.आर. में 365.701 कि.मी. राज्य मार्गों का अनुरक्षण।
- रु. 126.56 करोड़ की लागत से 467 मजरों का विद्युतीकरण।

- रु. 92 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित 220 के.वी. उपकेन्द्र छाता का निर्माण/ऊर्जीकरण कार्य।
- रु. 88.22 करोड़ मथुरा शहर से पीलीभीत भरतपुर मार्ग पर यमुना नदी में सेतु का निर्माण।
- रु. 71.47 करोड़ की लागत से 10.40 कि.मी. की लम्बाई के राधाकुण्ड बाई–पास का निर्माण कार्य।
- रु. 55 करोड़ की लागत से वृन्दावन (सुनरख बांगर) में वृद्ध माताओं के लिए कृष्ण कुटीर आश्रम का निर्माण।
- रु. 26.91 करोड़ से विश्व बैंक सहायतित उ.प्र. प्रो–पुअर पर्यटन विकास परियोजना के अन्तर्गत श्री बॉकेबिहारी मंदिर के समीपस्थ क्षेत्र का विकास कार्य।
- रु. 25.23 करोड़ की लागत से निर्मित 132 के.वी. उपकेन्द्र सौंख रोड़ का निर्माण कार्य।
- रु. 22.41 करोड़ मथुरा शहर में नया बस अड्डा मार्ग पर उपरिगामी सेतु का निर्माण।
- रु. 19.85 करोड़ से त्वरित आर्थिक विकास के अन्तर्गत 52 सड़कों का निर्माण कार्य।
- रु. 16.01 करोड़ से जुबली पार्क, डैम्पीयर नगर, मथुरा में मल्टीलेवल भूमिगत पार्किंग, स्ट्रीट वेण्डर्स के स्थान तथा ओपन एम्फीथियेटर का निर्माण।
- रु. 11.73 करोड़ से गोवर्धन बस स्टैण्ड के पुनर्विकास के अन्तर्गत कार स्टैण्ड ब्लॉक, क्लॉक रूम, टॉयलेट आदि का निर्माण/विकास कार्य।
- रु. 11.40 करोड़ से छः भागों में 7818 मी. लम्बाई में वृन्दावन परिक्रमा मार्ग का सुदृढीकरण एवं उच्चीकरण का कार्य किया गया है।

वृन्दावन परिक्रमा मार्ग का सौन्दर्यीकरण/विकास कार्य।

- रु. 13 करोड़ की लागत से निर्मित 04 स्थानों पर 33/11 के.वी. उपकेन्द्रों का निर्माण कार्य।
- रु. 10.00 करोड़ लागत से पं. दीनदयाल उपाध्याय सभागार का निर्माण दुवासु मथुरा।
- रु. 9.77 करोड से पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार की प्रासाद योजना के अन्तर्गत वृन्दावन में टूरिस्ट फैसिलिटेशन सेन्टर का निर्माण कार्य।

वृन्दावन स्थित टूरिस्ट फैसीलिटेशन सेन्टर

- रु. 7.49 करोड से सौंख रोड से बैकुण्ठधाम, महाराजा एस्टेट, संगम व शिवासा एस्टेट कॉलोनियों से होते हुये गोवर्धन रोड से मिलाने वाले मार्ग का निर्माण व नाले का निर्माण कार्य।
- रु. 5.12 करोड से गोवर्धन परिक्रमा मार्ग सी.सी.टी.वी. कैमरे पी.ए. सिस्टम एवं वाई–फाई सिस्टम की आपूर्ति एवं स्थापना का कार्य।
- रु. 4.77 करोड से श्री गिरिराज गोवर्धन परिक्रमा मार्ग में सुव्यवस्थित पेयजल व्यवस्था के लिए पाइप लाइन बिछाने एवं टीटीएसपी का निर्माण कार्य।
- रु. 3.90 करोड से गोवर्धन में बड़ी परिक्रमा मार्ग पर फेसिंग सम्बन्धी विकास कार्य।

गोवर्धन परिक्रमा मार्ग में फेंसिंग सम्बन्धी विकास कार्य

- रु. 3.47 करोड से गोवर्धन में छोटी परिक्रमा मार्ग पर फेसिंग सम्बन्धी विकास कार्य।
- रु. 3.35 करोड से एन.एच.–2 पर हीरा फूड के पास कुँज नगर होते हुये ग्राम कोटा से वापिस एन.एच.–2 तक सड़क सुदृढ़ीकरण एवं नाली निर्माण कार्य।
- रु. 1.98 करोड से गोकुल स्थित रसखान समाधि में इंटरप्रिटेशन सेन्टर का पुनर्विकास तथा जनसुविधा केन्द्र का निर्माण कार्य।
- रु. 1.85 करोड से जनपद मथुरा स्थित रसखान समाधि स्थल का पुनर्निर्माण सौन्दर्यीकरण व रसखान व महावन का विद्युतीकरण का कार्य। (सिविल कार्य)
- रु. 1.81 करोड से नन्दगॉव में रंगीली चौक से नन्द मंदिर तक जाने वाली वैकल्पिक सीढियों का पुनर्निर्माण का कार्य।
- रु. 1.77 करोड से जनपद मथुरा के गोकुल तिराहे से चिन्ताहरण महादेव तक प्रकाश व्यवस्था का कार्य।
- रु. 1.72 करोड से गोवर्धन में बड़ी परिक्रमा मार्ग पर आर.सी.सी. ह्यूम पाइप डालने का कार्य।
- रु. 1.66 करोड से जनपद मथुरा

नन्दगांव में वैकल्पिक सीढ़ियों का पुनर्निर्माण कार्य

में बरसाना–गोवर्धन रोड स्थित लोक निर्माण के गेस्ट हाउस की भूमि पर फैसीलिटेशन सेन्टर एवं पार्किंग का निर्माण कार्य।

- रु. 1.47 करोड से कृष्णापुरी चौराहे से डीग गेट चौराहे तक सड़क सुदृढ़ीकरण का कार्य।
- रु. 1.43 करोड से गोवर्धन में छोटी परिक्रमा मार्ग पर आर.सी.सी. ह्यूम पाईप डालने का कार्य।
- रु. 1.36 करोड से गोवर्धन चौराहे से महाराजा पार्क कॉलौनी का पहुँच मार्ग/लिंक मार्ग तथा जल निकासी हेतु नाले का निर्माण कार्य।
- रु. 1.25 करोड से गोवर्धन बस स्टैंड के सामने पीडब्ल्यूडी निरीक्षण भवन की भूमि पर कंट्रोल रूम, मीटिंग हॉल तथा वी.आई.पी. गेस्ट हाउस का निर्माण कार्य।
- रु. 1.14 करोड से गोकुल बैराज रोड से आर.टी.ओ. कार्यालय होते हुये सी.आर.पी.एफ. कैम्प तक सड़क व नाली का निर्माण कार्य।
- रु. 1.4797 करोड़ से कृष्णापुरी चौराहे से डीग गेट चौराहे तक सड़क सुदृढ़ीकरण।
- रु. 4.18 करोड़ से गोवर्धन में बड़ी परिक्रमा मार्ग में फैंसिंग लगाने कार्य।
- रु. 3.74 करोड़ से गोवर्धन में छोटी परिक्रमा मार्ग में फैंसिंग लगाने कार्य।
- रु. 1.60 करोड़ से किसानों को पशुधन की उपयोगिता हेतु तकनीकी प्रसार केन्द का निर्माण।
- रु. 1.50 करोड़ से बंजारा संस्कृति को बढावा देने हेतु उदासीन आश्रम जयसिंह पुरा, वृन्दावन रोड मथुरा का जीर्णोद्वार व भवन निर्माण।
- रु. 1.35 करोड़ रु. से पशुधन की उन्नत उत्पादकता के लिए जैव जलवायु विज्ञान प्रयोगशाला की स्थापना।
- रु. 1.34 करोड़ से अपशिष्ट प्रबंधन के अन्तर्गत प्लाण्ट एवं डम्पिंग कार्य।
- रु. 98.24 लाख से मथुरा के विभिन्न स्थलों पर प्रकाश की व्यवस्था कार्य।

- रु. 85.00 लाख से कोसी कलां में राष्ट्रीय राजमार्ग से बस स्टेशन/रेलवे स्टेशन जाने वाले मार्ग का सुदृढ़ीकरण कार्य।
- रु. 79.78 लाख से एन.एच.–02 से पुष्पांजलि उपवन गेट तक पहुँच मार्ग सुदृढीकरण।
- रु. 76.23 लाख से एकता मार्ग पर दो पार्किंगों का निर्माण।
- रु. 67.13 लाख से पुष्पांजलि द्वारिका गेट से ताराधाम होते हुए आशा कॉन्वेन्ट स्कूल तक सड़क व नाली का निर्माण।
- रु. 65.92 लाख से स्थित भाण्डीरवन का जीर्णोद्वार एवं सौन्दर्यीकरण।
- रु. 62.75 लाख से दीनदयाल धाम में सड़कों का सुदृढ़ीकरण।
- रु. 56.72 लाख से नवादा स्थित प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालय की जल निकासी हेतु नाले का निर्माण कार्य।
- रु. 55.52 लाख से नरहौली चौराहे से मिलिट्री क्षेत्र तक सड़क सुदृढ़ीकरण।
- रु. 52.09 लाख से मथुरा साइनेज बोर्ड लगाये गये।
- रु. 43.95 लाख से टैकमेनसिटी, नवादा, अडूकी मार्ग नाले एवं सड़क मरम्मत का कार्य।
- रु. 43.69 लाख से पागल बाबा हॉस्पिटल से चैतन्य विहार फेस–2 रेलवे लाईन तक सड़क व नाली का निर्माण।
- रु. 43.12 लाख से स्थित भाण्डीरवन जाने वाली सड़क का सुदृढीकरण।
- रु. 40.68 लाख से कैलाश नगर, मसानी, सिविल लाइन्स आवासीय योजना में एल.ई.डी. स्ट्रीट लाइट्स लगाना।
- रु. 37.76 लाख से चैतन्य विहार वृन्दावन स्थित 100 फीट चौडे मास्टर प्लान रोड के आर. ओ.बी. पर बी.सी.।

पशु पालन विभाग

- 3.06 करोड़ रूपये की धनराशि से वेटनरी यूनिवर्सिटी (दुवासु) में उ0प्र0 की पहली बकरी नस्ल सुधार हेतु आधुनिक बकरी प्रक्षेत्र की स्थापना।

- रु. 90 लाख से हरे चारे को संरक्षित करने हेतु ईकाई की स्थापना।
- 2.40 करोड़ से 2 वृहद गौसंरक्षण केन्द्रो का निर्माण।
- 11.83 करोड़ की लागत से नगरीय निकायों में कुल 06 कान्हा गौशालाओं का निर्माण।
- कुल 8886 निराश्रित बेसहारा गौवंश को संरक्षित किया गया।
- 760785 पशुओं का कृत्रिम गर्भाधान।
- 10216041 विभिन्न प्रकार के टीके पशुओं को लगाये गये।

विद्युत विभाग

- जिले में शहरी क्षेत्र में 24 घण्टे विद्युत आपूर्ति की जा रही है।

- 11194 क्षतिग्रस्त ट्रांसफार्मरों के स्थान पर नए ट्रांसफार्मर स्थापित।
- 23343 विद्युत बिल शिकायतों का निस्तारण।
- 3482 निजी नलकूपों को ऊर्जीकृत किया।
- सौभाग्य योजना के अन्तर्गत 0.14 लाख नए संयोजन से लाभान्वित।
- उजाला योजना के अंतर्गत 411629 ऊर्जा दक्ष एल.ई.डी. बल्बों का वितरण किया।
- पं. दीनदयाल उपाध्याय सोलर स्ट्रीटलाइट योजना के अन्तर्गत रु. 0.7012 करोड से 313 सोलर स्ट्रीटलाइट स्थापित।

कृषि विभाग

- किसान ऋण मोचन योजना में रु. 424.269 करोड से 65653 किसान लाभान्वित।
- प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में रु. 119.7064 करोड़ से 199511 किसान लाभान्वित।
- प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अन्तर्गत 102147 बीमित कृषको को 232.398 करोड़ की धनराशि से लाभान्वित किया जाना।
- रु. 10.19 करोड़ से 3098.97 किमी. नहरों की लम्बाई में सिल्ट सफाई कार्य पूर्ण कराकर कृषकों को सिंचाई सुविधा से लाभान्वित किया गया है।
- डी.बी.टी. के माध्यम से कुल 31 हजार 300 कृषकों को विभिन्न योजनाओं में 16.681 करोड़ की धनराशि खातों में स्थानन्तरित की गयी।

चिकित्सा विभाग

- 2.10 करोड़ रूपये की लागत से कुल 30 हेल्थ एण्ड बेलनेस सेन्टर का निर्माण।
- प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (आयुष्मान भारत) में 111378 परिवार लाभान्वित एवं 78436 गोल्डन कार्ड वितरित ।

- रु. 1.54 करोड़ की धनराशि से जननी सुरक्षा योजना के तहत 12498 महिलाएं लाभान्वित हुई।
- 7858 परिवारों को मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के अन्तर्गत पंजीकरण।

खाद्य एवं रसद विभाग

- उज्जवला योजना के अन्तर्गत 203281 लाभार्थियों को गैस कनेक्शन से लाभान्वित।
- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अन्तर्गत 917031 लाभार्थियों को ई –पॉस मशीन से खाद्यान्न वितरण।
- गत तीन वर्षों में 144755 मी0टन गेंहू की खरीद की गयी।
- गत तीन वर्षों में 6159 मी0टन धान की खरीद की गयी।

ग्राम्य विकास विभाग

- प्रधानमंत्री सड़क योजना में रु. 78.412 करोड से 140.395 किमी0 सडक का निर्माण।
- प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) में रु. 16.21 करोड से 1351 आवासों का निर्माण।

पंचायत राज विभाग

- स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) में रु. 196. 94 करोड से 164119 शौचालयों का निर्माण।
- राज्य वित्त आयोग के अन्तर्गत रु. 6033. 42 लाख व्यय कर 8503 विभिन्न कार्य।
- 14वें वित्त आयोग में रु. 28146.29 लाख व्यय कर 15596 कार्य।
- 389.7 लाख रुपये से 16 अन्त्येष्ठि स्थलों का निर्माण।
- 87.30 लाख रुपये से 5 बहुउद्देशीय पंचायत भवनों का निर्माण।

महिला कल्याण

- कन्या सुमंगला योजना के अन्तर्गत रु. 0.27 करोड़ से 1549 बालिकायें लाभान्वित।

समाज कल्याण

- रु. 1.18736 करोड़ की धनराशि से सामाजिक उत्पीड़न योजना में 1721 उत्पीड़ितों की आर्थिक मदद।
- मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अन्तर्गत 1926 जोड़े लाभान्वित।
- शादी अनुदान योजना के अंतर्गत 10.172 करोड़ की धनराशि से कुल 5086 लाभार्थियो को लाभान्वित किया गया।

दैवीय आपदा

- प्राकृतिक आपदा से प्रभावित कुल 32411 व्यक्तियों को 17.18 करोड़ की आर्थिक सहायता प्रदान की गयी।

श्रमिक कल्याण

- प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के अंतर्गत 5322 श्रमिक लाभान्वित।
- नेशनल पेंशन योजना ट्रेडर्स के अंतर्गत 137 ट्रेडर्स लाभान्वित।

सिंचाई विभाग

- सिंचाई विभाग में विगत तीन वर्षों में 3098 कि.मी. लम्बाई में नहरों की सिल्ट सफाई का कार्य रु. 10.19 करोड़ की लागत से पूर्ण कराकर कृषकों को सिंचाई सुविधा से लाभान्वित किया गया है।

विधान सभावार उपलब्धियां/विवरण

मथुरा

हेमा मालिनी
सांसद, मथुरा

श्रीकान्त शर्मा
विधायक, मथुरा

सांसद निधि से कराये गये कार्य

- रु. 11.732 लाख से 59 सोलर लाइट स्थापित।
- रु. 28.14 लाख से 67 मोटर/बैटरी चालित साइकिल दिव्यांगजनों उपलब्ध करायी।
- रु. 4.99633 लाख से मथुरा–वृन्दावन के ग्राम गणेशरा में नरेश मुखिया के मकान से बीरी प्रजापति के मकान तक 116 मीटर लम्बाई में इण्टर लोकिंग कार्य।
- रु. 4.99676 लाख से मथुरा–वृन्दावन के ग्राम देवीपुर में अशोक पटेल के मकान से भगवान सिंह के मकान तक 118 मीटर लम्बाई में इण्टर लोकिंग कार्य।
- रु. 5.10721 लाख से ग्राम मुरसदपुर (दामोदपुरा) में श्री नरेन्द्र बाबू के घर से श्री अशोक कुमार सैनी के घर तक 119 मीटर लम्बाई में सी.सी. रोड़ व नाली निर्माण कार्य।
- रु. 6.99490 लाख से जिला चिकित्सालय, मथुरा में ईमरजेंसी ब्लॉक से ऑपरेशन थियेटर/सर्जीकल वार्ड तक मरीजो को ले जाने हेतु कॉरीडोर का निर्माण कार्य।
- रु. 5.93382 लाख से मथुरा छावनी में नई बस्ती केन्द्रीय विद्यालय के पीछे गेट राजकुमार बाल्मिकी के घर से सैनी मोहल्ला तक 100 मीटर लम्बाई में सी.सी. रोड़ निर्माण कार्य।
- रु. 5.78310 लाख से कृष्ण कुंज कालौनी मथुरा में ट्रान्सफार्मर से राधेकृष्ण जूनियर हाईस्कूल तक 103 मीटर लम्बाई में सी.सी. रोड व नाली निर्माण कार्य।
- रु. 11.330 लाख से महेन्द नगर पालीखेड़ा मथुरा में एन0एच0–2 से वकील के मकान तक 225 मीटर लम्बाई में सी.सी. रोड़ निर्माण कार्य।
- रु. 4.47134 लाख से ग्राम द्वारकेश नगर बांकलपुर में ताराचन्द्र ठाकुर के मकान से बाबूलाल फौजी के मकान तक 79 मीटर लम्बाई में सी.सी. रोड़ व नाली निर्माण कार्य।
- रु. 4.68150 लाख से ग्राम नवादा में लाखन के मकान से रमेश चन्द्र के मकान तक 108 मीटर लम्बाई में सी.सी. रोड़ व नाली निर्माण कार्य।
- रु. 18.000 लाख से के.आर. गर्ल्स डिग्री कालेज मथुरा में तीन कक्ष निर्माण कार्य।

- रु. 7.450 लाख से के.आर. गर्ल्स डिग्री कालेज मथुरा में फर्नीचर खरीदने का कार्य।।
- रु. 3.915 लाख से श्रद्धानन्द प्रा.विद्यालय झींगुरपुरा वार्ड नं0 23 मथुरा में टॉयलेट ब्लाक व बाउण्ड्रीवाल का निर्माण कार्य।
- रु. 11.145 लाख से जनपद मथुरा के ग्राम अरहेरा में मैन रोड से बहादुर सिंह तक 253 मीटर लम्बाई में सी.सी. रोड़ निर्माण कार्य।
- रु. 8.061 लाख से ग्राम गणेशरा की केशव कुंज कालौनी में सचिन गौतम के घर से भगवत के घर तक 93 मीटर लम्बाई में इण्टर लोकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।।
- रु. 10.434 लाख से ग्राम रावल ब्लाक बल्देव मथुरा में 4 नग पुरूष, 4 नग महिला टॉयलेट ब्लाक का निर्माण कार्य।
- रु. 5.82074 लाख से विकास नगर मथुरा में गोपाल प्रसाद शर्मा के मकान से श्री विजय सैनी के मकान की ओर 123 मीटर लम्बाई में इण्टर लोकिंग सड़क निर्माण कार्य।
- रु. 8.85606 लाख से नवनीत नगर मथुरा में यूनिस मुल्लाह के मकान से सर्वेश कालेज की ओर 195 मीटर लम्बाई में इण्टर लोकिंग सड़क निर्माण कार्य।
- रु. 4.91564 लाख से ग्राम पंचायत बांकलपुर के हंसराज नगर में खजानी के मकान से विशाल के मकान की ओर 106 मीटर लम्बाई में इण्टर लोकिंग सड़क निर्माण कार्य।
- रु. 5.04000 लाख से वृन्दावन मथुरा के कैमार वन में उड़ियाबाबा रोड़ पर गोविन्द मठ से अबधूत आश्रम की ओर 88 मीटर लम्बाई में इण्टर लोकिंग सड़क निर्माण कार्य।
- रु. 5.99169 लाख से वार्ड नं0 22, हंसराज कालौनी मथुरा में गिरधरपुर रोड से राकेश सूरजमुखी के मकान से होते हुए हरद्वारी वकील के मकान तक 106 मीटर लम्बाई में सी. सी. सड़क निर्माण कार्य।
- रु. 5.997 लाख से ग्राम पंचायत नगला बोहरा में पवन के घर से खज्जो के घर तक 122 मीटर लम्बाई में सी.सी. सड़क निर्माण कार्य।
- रु. 6.000 लाख से मोतीकुंज कालोनी मथुरा में प्लाट नं0 ए–112 पर सामुदायिक भवन हाल का निर्माण कार्य।
- रु. 5.000 लाख से मथुरा–वृन्दावन महानगर पालिका के वार्ड नं0 54 में स्थिति अम्बेडकर बगीची में सामुदायिक भवन का निर्माण कार्य।
- रु. 5.97622 लाख से डिफेन्स कालोनी में ट्रान्सफार्मर गली में ट्रान्सफार्मर से रवी शर्मा के मकान तक 100 मीटर सी.सी. रोड़ निर्माण कार्य।
- रु. 6.959 लाख से मथुरा–वृन्दावन महानगर पालिका के अन्तर्गत श्री रवीन्द्र पाण्डेय (पूर्व अध्यक्ष नगर पालिका) के घर से मुख्य सडक तक 121 मीटर लम्बाई में सी.सी. सड़क,

नाली का निर्माण कार्य।(अनु0जाति क्षेत्र) ।

- रु. 5.99378 लाख से ग्राम मघेरा में दीन दयाल के मकान से बगीची तक 181 मीटर लम्बाई में सी.सी. सड़क निर्माण कार्य।
- रु. 5.83549 लाख से ग्राम गिरधरपुर, वार्ड नं0 03 में धर्मसिंह नेता जी के घर से महाराजा स्टेट कॉलोनी के गेट के तिराहे तक 110 मीटर लम्बाई में सी.सी.सड़क निर्माण कार्य।
- रु. 6.98784 लाख से नगर निगम मथुरा वृन्दावन में महेन्द्र नगर मौजा पालीखेडा के समोला टीला की ओर पूर्व निर्मित मार्ग के शेष भाग में बच्चू की दुकान से चामड माता मन्दिर तक 91 मीटर लम्बाई में सी.सी. सडक निर्माण कार्य।
- रु. 6.000 लाख से ग्राम जुल्हैंदी में ओमप्रकाश गुसाई के घर से रघुवीर (रग्गो) के घर तक 111 मीटर लम्बाई में सी.सी. निर्माण कार्य।
- रु. 4.000 लाख से ग्राम शाहपुर–चैनपुर के भाग बेरूका में ठा0 भगवान सिंह के मकान से विजेन्द्र पुत्र प्रहलाद सिंह के मीठे पानी के कुंआ तक 170 मीटर लम्बाई में ईट खडन्जा निर्माण कार्य।
- रु. 4.93851 लाख से वार्ड नं0 37 महोली में महोली गॉव वाली सडक से महेश मिस्त्री के मकान तक 85 मीटर लम्बाई में सी.सी.सडक निर्माण कार्य(अनु.जाति क्षेत्र)।
- रु. 5.000 लाख से ग्राम महोली में पप्पन ठाकुर के घर से रमना ठाकुर के घर तक 85 मीटर लम्बाई में सी.सी. सड़क निर्माण कार्य।
- रु. 4.98951 लाख से नगर निगम मथुरा–वृन्दावन के अन्तर्गत दामोदरपुरा वार्ड नं0 36 में भारत गैस गौदाम के सामने चौबे जी के घर से रणवीर जी के घर तक 97 मीटर लम्बाई में सी.सी.सडक निर्माण कार्य।
- रु. 4.95000 लाख से ग्राम नगला कुम्हेरिया में बीच गॉव में आम रास्ता 115 मीटर लम्बाई में सी.सी. सडक निर्माण कार्य।
- रु. 3.48980 लाख से ग्राम सकना के आरम्भ मन्दिर से कुँआ तक 155 मीटर लम्बाई में सी. सी. सड़क निर्माण कार्य।
- रु. 5.995 लाख से ग्राम तोष ब्लाक मथुरा में प्राथमिक पाठशाला से पथवारी देवी के मन्दिर तक 90 मीटर लम्बाई में सी.सी. सड़क निर्माण कार्य।
- रु. 8.000 लाख से नगला माना, ग्राम पंचायत उस्फार में सामुदायिक भवन निर्माण कार्य।
- रु. 10.000 लाख से मथुरा–वृन्दावन नगर निगम के वार्ड नं0 46 में बी0एस0ए0 ऑफिस के बरावर से नटवर नगर तक 260 मीटर लम्बाई में सी.सी. सडक निर्माण कार्य।
- रु. 3.000 लाख से नगर निगम मथुरा–वृन्दावन के वार्ड नं0 13 के अन्तर्गत महाराजा

अग्रसेन घाट लक्ष्मीनगर मथुरा में एक सामुदायिक भवन हॉल का निर्माण कार्य।

- रु. 50.000 लाख से केरल के वाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में पुर्नवासन/राहत कार्यो हेतु आपदा राहत कोष में सांसद निधि से मु0 50.00 लाख रु. की धनराशि का हस्तान्तरण।
- रु. 20.000लाख से मुख्य चिकित्सा अधिकारी, मथुरा के अन्तर्गत जिला अस्पताल मथुरा को सेना अस्पताल मथुरा द्वारा संचालन हेतु एक क्रिटिकल केयर एम्बुलेंस की आपूर्ति का कार्य।
- रु. 6.99998 लाख से ग्राम पंचायत वृन्दावन बांगर में मास्टर जी के मकान से देवी चित्री विचित्री के मकान तक 170 मीटर लम्बाई में सी.सी.सडक निर्माण कार्य।
- रु. 10.27043 लाख से जनपद मथुरा में अग्रवाल लाइफ लाइन हॉस्पीटल के पीछे वाली गली में संजीव वर्मा के मकान से चौधरी रनधीर सिंह के मकान के आगे से बेराज रोड़ तक 166 मीटर लम्बाई में सी.सी. स़क निर्माण कार्य।
- रु. 5.995 लाख से ग्राम भदाल सुन्दर में मदन मास्टर के मकान से मोहर सिंह के मकान तक 133 मीटर लम्बाई में सी.सी. सड़क निर्माण कार्य।
- रु. 3.98824 लाख से नगर निगम मथुरा वृन्दावन के वार्ड नं0 26 के अन्तर्गत इन्दूपुरम कालौनी के सी. ब्लाक में अनिल चौधरी के घर से मिथिलेस कुमार के घर मे 58 मीटर लम्बाई में सी.सी. सडक निर्माण कार्य।
- रु. 5.500 लाख से गांव बडोता में श्री जवाहर के घर से प्राथमिक पाठशाला तक 100 मीटर लम्बाई में सी.सी.सडक निर्माण कार्य।
- रु. 12.051 लाख से मथुरा–वृन्दावन मार्ग से धौरेरा रेलवे क्रासिंग तक 226 मीटर लम्बाई में सी.सी. रोड़ एवं नाली निर्माण कार्य।
- रु. 7.26487 लाख से ग्राम पालीखेड़ा में महेन्द्र नगर फेस–2 सौख रोड़ द्वारकेश मार्केट के बराबर वाली गली में जुगेन्द्र सिंह की फेक्ट्री तक 80 मीटर लम्बाई में सी.सी. रोड़ व नाली निर्माण कार्य।
- रु. 4.53050 लाख से कृष्णा नगर मथुरा में मधुवन इन्कलेव में आदेश शर्मा के घर से जैन फर्नीचर शौरूम के मध्य डा0 डी0पी0गोयल जी की आफिस के सामने 97 मीटर लम्बाई में सी.सी. रोड़ निर्माण कार्य।
- रु. 5.999 लाख से ग्राम मुखराई, में पप्पू ठाकुर के घर से श्री प्रहलाद के घर तक 104 मीटर लम्बाई में सी.सी. सड़क निर्माण कार्य।
- रु. 7.99498 लाख से ग्राम नौगरा बाद के गौधूलीपुरम में सतीश उपाध्याय के मकान से रावत के मकान तक सी.सी. सड़क निर्माण कार्य।।

- रु. 5.19957 लाख से गॉव बसौती में जहीर बाबा मन्दिर से नहर तक 105 मीटर लम्बाई में सी.सी.सडक निर्माण कार्य।
- रु. 4.494 लाख से श्रीमती शान्ती देवी प्राथमिक विद्यालय एवं ग्वाल प्राथमिक विद्यालय बाढ़पुरा कालौनी सदर बाजार में शौचालय एवं बाउण्ड्रीवाल का निर्माण कार्य।
- रु. 6.92565 लाख से ब्रज बिहार कालोनी, सौख रोड़ मण्डी समिति, कृष्णा नगर में प्रजापति ब्रह्मकुमारी ईश्वरी विश्व विद्यालय सेवा केन्द्र के सामने 77 मीटर लम्बाई में सी. सी. सड़क निर्माण कार्य।
- रु. 3.99882 लाख से वार्ड नं0 22, वाकलपुर में स्थित अमर कॉलोनी, मथुरा में कृष्णवीर सिंह चौहान के घर से राकेश सौनी के घर तक 80 मीटर लम्बाई में सी.सी. सड़क निर्माण कार्य।
- रु. 4.990 लाख से ग्राम महोली, डिफेन्स कॉलोनी, वार्ड नं0 37 मथुरा में अनिल शर्मा के घर से राधा बल्लभ के घर तक 100 मीटर लम्बाई में सी.सी. सड़क निर्माण कार्य।
- रु. 5.95000 लाख से ग्राम जिखन गांव में कमल किशोर के घर से जनरल स्टोर तक 140 मीटर लम्बाई में सी.सी. सड़क निर्माण कार्य।
- रु. 5.900 लाख से ग्राम कौनई में गोविन्दा के मकान से पेलखू रोड की तरफ 85 मीटर लम्बाई में सी.सी. सड़क निर्माण कार्य।
- रु. 5.98197 लाख से ग्राम उमरी में लीला के घर से लक्ष्मन के घर तक 105 मीटर लम्बाई में सी.सी. सड़क निर्माण कार्य।
- रु. 43.26375 लाख से अन्य विविध कार्य।

विधायक निधि से कराये गये कार्य

- रु. 2.50 लाख से ग्राम पंचायत सकराया के नगला बिहारी (बाबूगढ सकराया) में पेयजल हेतु अधिष्ठापित टीटीएसपी के टैंक एवं पाइप लाइन के कार्य।
- रु. 3.090 लाख से प्रा.वि.औरंगाबाद प्रथम में डेस्क बैंच अवस्थापना का कार्य।
- रु. 3.25444 प्रा.वि.औरंगाबाद द्वितीय में डेस्क बैंच अवस्थापना का कार्य।
- रु. 5.17 लाख से मथुरा वृन्दावन नगर निगम के अन्तर्गत प्राथमिक विद्यालय बाबूगढ़ में 500 एल.पी.एच. आर.ओ.वाटर प्लांट,सबमर्सिबल पम्प एवं चिलर प्लांट 300 लीटर।
- रु. 5.17 लाख से मथुरा वृन्दावन नगर निगम के अन्तर्गत पूर्व माध्यमिक विद्यालय सकराया में 500 एल.पी.एच. आर.ओ.वाटर प्लांट,सबमर्सिबल पम्प एवं चिलर प्लांट 300 लीटर।
- रु. 5.17 लाख से मथुरा वृन्दावन नगर निगम के अन्तर्गत प्राथमिक विद्यालय नगला

बिहारी में 500 एल.पी.एच. आर.ओ.वाटर प्लांट,सबमर्सिबल पम्प एवं चिलर प्लांट 300 लीटर।

- रु. 4.200 लाख से प्रा.वि. औरंगाबाद/पूर्व मा.वि. औरगांबाद–2 में आर.ओ. चिलर प्लान्ट (500एलपीएच) एवं समरसेविल पम्प की स्थापना कार्य।
- रु. 4.200 लाख से प्रा.वि.अडूकी–2 में आर.ओ. चिलर प्लान्ट (500एलपीएच) एवं समरसेविल पम्प की स्थापना कार्य।
- रु. 4.200 लाख से प्रा.वि./पू.मा.वि. छरौरा में आर.ओ. चिलर प्लान्ट (500एलपीएच)एवं समरसेविल पम्प की स्थापना कार्य।
- रु. 3.570 लाख से प्रा.वि. महोली में आर.ओ. (500एलपीएच) एवं चिलर प्लान्ट की स्थापना कार्य।
- रु. 2.1420 लाख से प्रा.वि./पू.मा.वि. नौगॉव (500एलपीएच) में आर.ओ. चिलर प्लान्ट की स्थापना कार्य।
- रु. 3.570 लाख से प्रा.वि.नरहौली–2/पू.मा.वि. नरहौली में आर.ओ., चिलर प्लान्ट (500एलपीएच) की स्थापना कार्य।
- रु. 4.200 लाख से प्रा.वि./पू.मा.वि. नवादा में आर.ओ., चिलर प्लान्ट (500एलपीएच)एवं सवमरसेविल पम्प की स्थापना कार्य।
- रु. 3.570 लाख से प्रा.वि. मन्साटीला पालीखेड़ा में आर.ओ., चिलर प्लान्ट(500एलपीएच) की स्थापना कार्य।
- रु. 3.570 लाख से प्रा.वि.विर्जापुर में आर.ओ., चिलर प्लान्ट (500एलपीएच)की स्थापना कार्य।
- रु. 75.6 लाख से 18 प्रा.वि./पू.मा.विद्यालयों में (500एलपीएच) में आर.ओ., चिलर प्लान्ट एवं सवमरसेविल पम्प की स्थापना कार्य।
- रु. 4.360 लाख से स्व0 मोहन पहलवान स्पोटर्स स्टेडियम, गनरेशरा मथुरा में 500 एल.पी. एच. प्लांट मय चिलर प्लांट अधिष्ठापन सम्बन्धी कार्य।
- रु. 4.980 लाख से प्रा.वि.अगनपुरा में आर.ओ. मय चिलर प्लान्ट–500–एलपीएच
- रु. 4.980 लाख से प्रा.वि./पूर्व मा.वि. मुकन्दपुर में आर.ओ. मय चिलर प्लान्ट–500–एलपीएच की स्थापना।
- रु. 4.980 लाख से प्रा.वि. राजपुर में आर.ओ. मय चिलर प्लान्ट–500–एलपीएच की स्थापना।
- रु. 4.980 लाख से प्रा.वि. नौबरामद में आर.ओ. मय चिलर प्लान्ट–500–एलपीएचकी स्थापना।

- रु. 2.530 लाख से प्रा.वि. सकराया में आर.ओ. मय चिलर प्लान्ट–150–एलपीएच की स्थापना।
- रु. 4.980 लाख से प्रा.वि. नगला चमारान/नं0सकराया में आर.ओ. मय चिलर प्लान्ट–500–एलपीएच की स्थापना।
- रु. 2.190 लाख से के0आर0 पी0जी0 कालेज मथुरा के पास सार्वजनिक स्थल पर 500 एल.पी.एच. आर.ओ. मय चिलर प्लांट की स्थापना।
- रु. 2.142 लाख से नगर आयुक्त कार्यालय (नगर निगम मथुरा वृन्दावन) के पास सार्वजनिक स्थल पर 500 एल.पी.एच. आर.ओ. मय चिलर प्लांट की स्थापना।
- रु. 147.794 लाख से 109 अन्य विविध कार्य।

त्वरित आर्थिक विकास निधि से कराये गये कार्य

- रु. 28.930 लाख से छरौरा में एन0एच0–2 से मार्ग जुगल सैनी के घर से महादेव मन्दिर तक सी.सी. रोड निर्माणकार्य।
- रु. 17.690 लाख से कोटा में मौजी के घर से रेलवे अन्डर पास तक सी.सी. रोड निर्माण कार्य।
- रु. 64.300 लाख से कोटा में कमल के मकान से सीताराम प्रधान के खेत तक डामरीकरण रोड निर्माण कार्य।
- रु. 27.730 लाख से बाकलपुर में श्रीजी गार्डन के सामने से सालिगराम चर्तुवेदी के घर से होते हयु मास्टर ओमप्रकाश के घर तक एवं रामौतार के घर तक सी.सी. रोड निर्माण कार्य।
- रु. 32.470 लाख से गणेशरा में किशनलाल के मकान से बाकलपुर बम्बे तक पेटिंग रोड निर्माण कार्य।
- रु. 7.630 लाख से पालीखेड़ा में योगेन्द्र चाहर के मकान से देवो के मकान सी.सी. रोड निर्माण कार्य।
- रु. 28.280 लाख से पालीखेडा में सौख रोड से बालाजी इन्कलेव से होते हये बन्तों के मकान तक सी.सी. रोड निर्माण कार्य।
- रु. 4.160 लाख से पालीखेड़ा में विष्णु के मकान से ड्राइवर के घर तक सी.सी. रोड निर्माण कार्य।
- रु. 9.800 लाख से नौगांव में तारा सिंह के मकान से चन्दन सिंह के मकान सी.सी. रोड निर्माण कार्य।
- रु. 19.870 लाख से अडूकी में वैन सिंह के मकान मस्जिद तक सी.सी. रोड निर्माण कार्य।

- रु. 16.360 लाख से अडूकी में प्राइमरी प्रथम से भवर सिंह के मकान तक सी.सी. रोड निर्माण कार्य।
- रु. 4.590 लाख से महोनपुर में तेज सिंह फौजी के घर से मुनीम के घर तक सी.सी. रोड निर्माण कार्य।
- रु. 3.920 लाख से अडूकी में जग्गी वाल्मीकि के मकान से नारायन दिवाकर के घर तक सी.सी. रोड निर्माण कार्य।
- रु. 12.430 लाख से नवादा आजमपुर में प्राइमरी विद्यालय से पुष्पांजलि द्वारिका गेट तक सी.सी. रोड निर्माण कार्य।
- रु. 28.840 लाख से नावादा मित्र नगर कॉलोनी में ए0के0 बघेल के मकान से ब्रजमोहन मास्टर के मकान से होते हुये बहादुर के मकान तक सी.सी. रोड निर्माण कार्य।
- रु. 4.470 लाख से नवादा में अनिल के मकान से शीशपाल के मकान कर सी.सी. रोड निर्माण कार्य।
- रु. 5.240 लाख से नवादा में दिगम्बर के मकान से निरंजन के मकान तक सी.सी. रोड निर्माण कार्य।
- रु. 3.590 लाख से नवादा में चन्द्रपाल के मकान से कृन्तपाल के मकान तक सी.सी. रोड निर्माण कार्य।
- रु. 3.740 लाख से नवादा में भिक्की के मकान से उदय के मकान तक सी.सी. रोड निर्माण कार्य।
- रु. 30.380 लाख से तन्तुरा में बालजी पुरम में बाकेंबिहारी जी के घर से रामकरन के घर तक सी.सी. रोड निर्माण कार्य।
- रु. 9.810 लाख से तन्तुरा में छत्रपाल के घर से ओमवीर के घर से होते हुये साहब सिह के घर तक सी.सी. रोड निर्माण कार्य।
- रु. 23.000 लाख से दामोदरपुरा में रवि बघेल के मकान से आर्मी की चाहरदीवारी तक सी. सी. रोड निार्मण कार्य।
- रु. 24.200 लाख से औरंगाबाद मे पप्पू के मकान से हरिश चन्द के घर से होते हुये बी0एस0 जैन के घर तक सी.सी. रोड निर्माण कार्य।
- रु. 24.640 लाख से औरंगाबाद में बैराज रोड से कब्रिस्तान होते हुये उस्मान सैयद तक सी.सी. रोड निर्माण कार्य।
- रु. 9.280 लाख से वृन्दावन बटाला मौहल्ले में सोनू गीतम के घर से देवेन्द्र के मकान तक सी.सी. रोड निर्माण कार्य।
- रु. 43.160 लाख से मुडेसी से दयाराम के घर से विजय के घर सी.सी. रोड निर्माण कार्य।

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश
6, पार्क रोड, लखनऊ–226001